Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 50
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
गुरूवार, 26 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 डीजल खरीद में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया ...

4 बांग्लादेश की नई सरकार में हिंदू मंत्रियों की ...

7 लगातार असफल हो रहे जोस बटलर के बचाव ..

संक्षिप्त न्यूज

Rahul Gandhi ने प्रदर्शनकारियों को कहा 'बब्बर-शेर', BJP का पलटवार- Congress खुद का मजाक बना रही है

नई दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के 'शर्टलेस विरोध प्रदर्शन' को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक बहस के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन पर उसी तरह पछतावा होना चाहिए जैसे उन्हें आपातकाल पर हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश इस शर्मनाक कृत्य को हमेशा याद रखेगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का यह उचित तरीका है? उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी पार्टी का मज़ाक बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की आलोचना करने और एआई समिट को मज़ाक बनाने से पहले, आप खुद का मज़ाक बना रहे हैं। क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का यही तरीका है? उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस पार्टी को इस पर उतना ही पछतावा होना चाहिए जितना उन्हें आपातकाल पर हुआ था - हमेशा के लिए। वे इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। देश उन्हें इस शर्मनाक हरकत की याद दिलाता रहेगा। यह घटना तब घटी जब भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट के भारत मंडपम स्थल पर समझौतावादी प्रधानमंत्री के नारे लिखते हुए अपनी कमीजें उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने असहमति जताने के लिए अपनी कमीजें उतारीं। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए 'कमरबंद विरोध प्रदर्शन' के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एक ही समय पर पश्चिम एशिया में मोदी और पूर्वी एशिया में योगी, विश्व के नेता का माथा चकराया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस आक्रामक और स्पष्ट विदेश नीति तथा निवेश कूटनीति का मॉडल अपनाया है, वह आज नए भारत की दिशा तय करता दिखाई दे रहा है। एक ओर मोदी वैश्विक मंच पर भारत की सामरिक स्वायत्तता, सुरक्षा साझेदारी और तकनीकी शक्ति का परचम लहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी राज्य को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सीधे दुनिया के निवेश केंद्रों में दस्तक दे रहे हैं। दोनों नेताओं के विदेश दौरे एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें भारत को वैश्विक शक्ति और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक इंजन बनाने का स्पष्ट रोडमैप नजर आता है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेल अवीव पहुँच कर पश्चिम एशिया की राजनीति में निर्णायक दस्तक देने वाले हैं। इजराइली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुखपृष्ठ पर छपी उनकी तस्वीर और हेडलाइन वेलकम मोदी इस बात का संकेत है कि यह दौरा सामान्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। मोदी इस बार इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। 2017 की अपनी

ऐतिहासिक यात्रा के बाद मोदी का यह दूसरा इजराइल दौरा है। इस बार एजेंडा और भी व्यापक है। रक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सहयोग और सीमा पार भुगतान प्रणाली जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई गहराई देने पर जोर है।

इस दौरे का निमंत्रण इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए मोदी को प्रिय मित्र कहा। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण को भारत इस बार रणनीतिक लाभ में बदलना चाहता है।

इजराइल की रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, जल संरक्षण और एग्री टेक्नोलॉजी में महारत भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत अब तकनीकी और सुरक्षा साझेदारी का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है इसलिए मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खास बात यह भी है कि पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत संतुलन साधते हुए इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। यह अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक स्पष्ट संकेत है कि नई दिल्ली अपनी सामरिक स्वायत्तता पर अडिग है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मुख्यमंत्री योगी ने सिंगापुर में गूगल, टेमासेक, जीआईसी, डीबीएस बैंक, ब्लैकस्टोन और डेटा सेंटर से जुड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें कीं। डेटा सेंटर, एग्री बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, सोलर एनर्जी, फिनटेक और स्टार्टअप निवेश पर बातचीत की गयी और बड़े निवेश प्रस्ताव यूपी ने हासिल किये। जापान में मुख्यमंत्री योगी ने सुजुकी, कुबोटा, तोशिबा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के साथ संवाद किया। यहां मुख्यमंत्री का ग्रीन हाइड्रोजन, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण पर जोर रहा।

योगी खुद को उत्तर प्रदेश का सीईओ बताकर सीधे निवेशकों से जी टू बी बैठकें कर रहे हैं। वह कानून व्यवस्था, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और 25 करोड़ आबादी की उपभोक्ता शक्ति को निवेश का आधार बना रहे हैं।

किसान महाचौपाल से Rahul Gandhi की हुंकार, 'PM Modi में दम है तो US Deal रद्द करके दिखाएं'

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी मंगलवार को भोपाल में अमेरिकी व्यापार समझौते के विरोध में एक भव्य 'किसान महाचौपाल' का आयोजन किया। किसान महाचौपाल को वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जमकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस साल इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, मुझे बीच में ही रोक दिया गया।

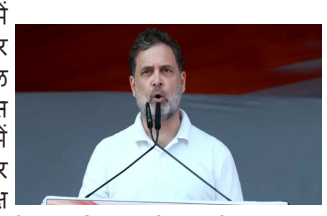

राहुल गांधी ने दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ सिंह को आदेश लेने के लिए फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अजीत डोवाल और एस जयशंकर ने भी जवाब नहीं दिया... युद्ध का फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, वे अपने कमरे में छिप गए और सेना प्रमुख से कहा कि वे जो चाहें करें... सेना प्रमुख ने लिखा है कि उस दिन भारतीय सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि यानी- जब आर्मी चीफ को ऑर्डर देने और चीन को रोकने का समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए।

गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पांच महीने तक रुका रहा क्योंकि इसमें कृषि और कृषि उत्पाद शामिल थे। भारत के किसान, खेत मजदूर और यहां तक ??कि सरकार भी इसे नहीं चाहती थी। शाम को संसद से निकलने के बाद मोदी ने ट्रंप को फोन किया... उन्होंने झूठ बोला, यह बहाना बनाया कि कांग्रेस की महिला सांसद हमला करने वाली हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सीधे फोन किया और कहा कि वह समझौता करने के लिए तैयार हैं।

अमेरिकी शुल्क घोषणा के बाद सौर कंपनियों के शेयर में 14 प्रतिशत से अधिक गिरावट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिका के कुछ भारतीय सौर उत्पादों पर 125.87 प्रतिशत का प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) लगाए जाने की घोषणा के बाद सौर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई पर वारी एनर्जीज लिमिटेड का शेयर 14.99 प्रतिशत लुढ़क गया जबकि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के शेयर में 14.23 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर में 7.47 प्रतिशत और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में 1.41 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारतीय सौर उत्पादों को सरकार द्वारा अनुचित सब्सिडी दी जा रही है जिसके कारण 125.87 प्रतिशत का प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क घोषित किया गया है। अमेरिकी आदेश के अनुसार, ''24 फरवरी 2026 को अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या नहीं (सोलर सेल), के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा की।'' ये शुल्क अमेरिकी प्रशासन द्वारा 24 फरवरी से सभी देशों पर घोषित 10 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त हैं।

अरुणाचल प्रदेश की युवतियों पर नस्लीय टिप्पणी करने वाली महिला गिरफ्तार, पति ने कहा- 'मुझे शर्मिंदगी है'

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली पुलिस ने आरोपी रूबी जैन को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर में किराएदार के तौर पर रहने वाली तीन नॉर्थ-ईस्ट महिलाओं को नस्लभेदी गालियां दीं और अपमानजनक बातें कहीं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच एक एसीपी-रैंक के अधिकारी कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के संबंधित नियम भी जोड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, 'एससी-एसटी एक्ट जोड़ने के बाद अब जांच एक एसीपी -रैंक के

अधिकारी को सौंपी गई है और सीनियर अधिकारी इसकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।' साथ ही, जैन के पति हर्ष सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जैन और अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तीन महिलाओं के बीच 20 फरवरी को उनके किराए के घर में रिपेयर के काम को लेकर बहस हो गई थी। इस झगड़े के वीडियो भी वायरल हो गए हैं, जिसमें जैन को तीनों महिलाओं को गालियां देते हुए देखा जा सकता है। पुलिस अब वीडियो की जांच कर रही है। सिंह ने कहा है कि कपल पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है, और कहा कि यह घटना गुस्से में हुई। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि कपल भी शर्मिंदा है, लेकिन लोगों से कहा कि वे उनकी बात भी सुनें और मीडिया ट्रेल्स से बचें। उन्होंने कहा, 'मुझे सोशल मीडिया पर मेरी मां की अश्लील एडिट की हुई तस्वीरें भेजी जा रही हैं, हमारे परिवार और प्रोफेशन को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए... मैं पर्सनली सभी नॉर्थईस्ट के लोगों से माफी मांगता हूं।' केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने एएनआई को बताया कि उनका ऑफिस भी तीनों लड़कियों के संपर्क में है, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस मामले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है।

पूसा मेला में गरजे मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की सब्सिडी में अब नहीं चलेगी कोई भी धांधली

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आईसीएआर-आईएआरआई परिसर में तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय कृषि को 'विकसित कृषि-आत्मनिर्भर भारत' की ओर ले जाने के उद्देश्य से व्यापक सुधार एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत की। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों के भुगतान में देरी, प्रक्रियात्मक अड़चनें और कमजोर निगरानी प्रणाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में आयोजित इस वार्षिक मेले का उद्घाटन एक औपचारिक वृक्षारोपण अभियान के साथ किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक एमएल जाट और आईएआरआई के निदेशक सी.एच. श्रीनिवास राव के

साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और संस्थागत प्रतिनिधि उपस्थित थे। नीति निर्माण में किसानों को प्राथमिकता देते हुए, चौहान ने किसानों के साथ मंच साझा किया और व्यक्तिगत रूप से एक दिव्यांग किसान की सहायता की, जिससे मंत्रालय द्वारा वर्णित किसान सर्वोपरि दृष्टिकोण को बल मिला। इस कार्यक्रम के दौरान सात किसानों को आईएआरआई कृषि अध्येता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बकाया भुगतान के संबंध में मंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों के भुगतान में देरी करने वाली किसी भी एजेंसी या राज्य सरकार को रोकी गई राशि पर 12इ ब्याज देना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य स्तर पर देरी होने की स्थिति में केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे अपना हिस्सा हस्तांतरित करने के लिए उपाय तलाशेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के धन को रोककर देरी से लाभ कमाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि मशीनीकरण और सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं पर चौहान ने बताया कि 18 से अधिक केंद्रीय योजनाएं राज्यों के माध्यम से लागू की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया कि लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। उन्होंने ऐसे मामलों का उदाहरण दिया जहां आवंटित धनराशि के बावजूद सूचीबद्ध लाभार्थियों को उपकरण प्राप्त नहीं हुए।

बिहार में बढ़ा अपराध : तेजस्वी का एनडीए पर हमला 'अपराधियों का राज, कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल'

पटना **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में अपराध में भारी वृद्धि और कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। हर दिन हत्याएं, बलात्कार और गोलीबारी हो रही है। इससे पता चलता है कि सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है... कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मौजूदा सरकार में अपराधियों का राज चल रहा है। सरकार में कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हों या दोनों उपमुख्यमंत्री, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार भी कमजोर पड़ गए हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने राज्य की राजनीतिक गतिशीलता

की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने राज्य का गृह मंत्रालय कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन अब उन्हें इसे भाजपा को देना होगा।

तेजस्वी यादव ने आत्मनिरीक्षण किए बिना कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि और जो लोग राज्य में अपराध की बात जोर-शोर से करते हैं, उन्हें पहले खुद को देखना चाहिए। कानून-व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे पहले सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार कानून का शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिन्हा ने कहा कि विपक्ष की अपनी भूमिका है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। उसे बिहार में रहना चाहिए, बिहार का दौरा करना चाहिए, तब उसे विकास दिखाई देगा। विपक्ष के नेता को ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह सरकार कानून का शासन स्थापित कर रही है।

पीएम मोदी की इजराइल यात्रा पर कांग्रेस का हमला खेड़ा ने पूछा- किसके कहने पर जाते हैं विदेश?

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय इजराइल दौरे पर पहुंचे। पीयूष गोयल की 'राहुल गांधी समझौता कर चुके हैं' वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए खेड़ा ने भाजपा से कहा कि वह पिछली सरकारों पर संदेह जताने के बजाय मौजूदा सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब दे।

एएनआई से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री किसके कहने पर विदेश जाते हैं? किसके दबाव में उन्होंने व्यापार समझौते पर सहमति जताई? सरकार में कौन है? अगर लोग हमसे नाराज हैं, तो यह उनके (जनता के) और हमारे बीच की बात है। अब, 12 साल सत्ता में रहने के बाद आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। एपस्टीन से आपका क्या संबंध है? आप क्यों डर रहे हैं?

प्रधानमंत्री मोदी अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए तेल अवीव, इजरायल पहुंच गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच 'मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी' को और गहरा करना है। यूनाइटेड किंगडम शिखर सम्मेलन में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी प्रधानमंत्री से भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सवाल उठाए। मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी से फिलिस्तीन के साथ जारी युद्ध को लेकर इजरायली संसद से भी सवाल करने को कहा।

'यह बदले की राजनीति है', भाई के घर एसीबी की छापेमारी पर भड़के जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री

श्रीनगर **(एजेंसी)**। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने भाई के आवास पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की छापेमारी के बाद उनका बचाव करते हुए कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। उन्होंने इस कार्रवाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व को बदनाम करने और डराने की एक सुनियोजित कोशिश बताया।

अधिकारियों ने बताया कि एसीबी ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जम्मू में चौधरी के भाई विजय सिंह के घर पर छापेमारी की। चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''यह लड़ाई शुरू हो गई है, और हम इसे कानूनी तौर पर लड़ेंगे। हमें भारत की न्यायपालिका और जम्मू-कश्मीर के कई अच्छे अधिकारियों पर भरोसा है जो इंसाफ पक्का करेंगे। अगर विजय सिंह गलत हैं, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए।''

जम्मू-कश्मीर पुलिस में निरीक्षक पद पर तैनात अपने भाई के सर्विस रिकॉर्ड का

बचाव करते हुए चौधरी ने कहा कि उन्होंने गुरसाई, थानामंडी, डोडा और सुपवाल में आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, और जहां भी उनकी तैनाती हुई, वहां उन्होंने आतंकवादियों और अपराधियों से मुकाबला करके साख बनाई है। चौधरी ने कहा, ''वह एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका पूरा करियर, इतिहास और सर्विस रिकॉर्ड आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लगातार लड़ाई को दिखाता है। उन्होंने जहां भी सेवाएं दीं, अपनी हिम्मत और पेशेवर तरीकों के लिए नाम कमाया।''

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इस छापेमारी को अपने परिवार को ''डराने और बदनाम करने'' की कोशिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग के आंतरिक कलह के कारण उनके भाई की पदोन्नति रुकी रही। उन्होंने कहा, ''ऊपर बैठे जो लोग सोचते हैं कि इस घर में कोई छिपा हुआ खजाना मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपने पहले की कार्रवाई देखी- अब तक क्या बरामद हुआ है? मेरे पास कई फाइलें आती हैं जिनमें लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और बाद में उन्हें बरी कर दिया जाता है।'' चौधरी ने कहा, ''हम डरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके लिए खड़े हैं। आखिर में सच की जीत होगी।

रोहित पवार का बड़ा आरोप, मुंबई पुलिस ने अजित पवार विमान हादसे पर एफआईआर की से किया इनकार

दिव्यांश

मुम्बई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार बुधवार को अजीत पवार विमान दुर्घटना मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने बताया कि पुलिस स्टेशन पहुंचने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत एक कनिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनसे बातचीत करने और उन्हें समझाने के बाद, अधिकारी एक लैपटॉप लाए और एफआईआर प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, इसके बाद एक उच्च पदस्थ अधिकारी, अतिरिक्त डीसीपी, वहां पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया।

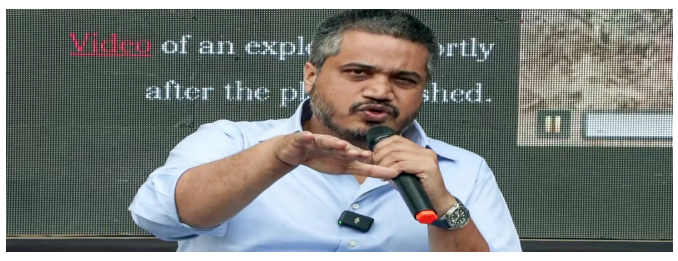

रोहित पवार ने कहा कि हम मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने आए थे। स्टेशन पहुँचने पर वहाँ एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी

मौजूद था - 'कनिष्ठ' का अर्थ है वह अधिकारी जिसे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। वरिष्ठ निजी जांच अधिकारी भी वहाँ थे। उनसे बात करने और उन्हें समझाने के बाद, वे एक लैपटॉप लाए और हमारी एफआईआर छापने की प्रक्रिया शुरू की। तभी एक उच्च अधिकारी, अतिरिक्त डीसीपी, आए और कहा कि यह एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए, नए कानून के अनुसार, किसी भी संज्ञेय अपराध से संबंधित एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यह इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।

इससे पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले, पवार ने कहा था कि एफआईआर कई पक्षों के खिलाफ दर्ज की गई हैं: वीएसआर के सहयोगी, डीजीसीए के संबंधित अधिकारी, उड़ान को मंजूरी देने वाली कंपनी एरो और एरो के वे अधिकारी जो राज्य सरकार से जुड़े हैं। पाँचवीं एफआईआर का नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि लोग इस मामले को आपराधिक साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीएसआर के सहयोगियों, इसमें शामिल डीजीसीए अधिकारियों, उड़ान की मंजूरी देने वाली कंपनी एरो और एरो समूह के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की योजना बना रहे हैं जिनका राज्य सरकार से संबंध है। पांचवीं एफआईआर में नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि लोग इसे आपराधिक साजिश का मामला बता रहे हैं।

उन्होंने वीएसआर की कंपनी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के बीच संबंधों का भी आरोप लगाया और दावा किया कि इन संबंधों के साथ-साथ कई भाजपा नेताओं के वीएसआर के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण वीएसआर के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद से यह स्पष्ट नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था या एक दुर्घटना थी, और इसकी जांच होनी चाहिए।

दिल्ली के वरिष्ठ कवि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी का मुंबई में भव्य स्वागत

मुम्बई ।काव्यसृजन न्यास एवं अखिल भारतीय काव्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली से पधारे वरिष्ठ कवि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी के सम्मान में सांताक्रुज ईस्ट, मुंबई स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉल में एक गरिमामय एवं भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता आ. हौसिला प्रसाद 'अन्वेषी' ने की तथा संचालन आ. ओमप्रकाश तिवारी ने प्रभावशाली ढंग से किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. डॉ दयानंद तिवारी, निडर जौनपुरी एवं सौ. कुसुम तिवारी 'झल्ली' की उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ी। संस्था द्वारा सभी अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।

अपने उद्बोधन में प्रो. डॉ दयानंद तिवारी ने कहा कि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी आज राष्ट्रीय ख्याति के कवि के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओंकार जी की काव्य साधना, वैचारिक गहराई और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत रचनाएँ उन्हें देशभर में विशिष्ट पहचान दिला रही हैं। डॉ तिवारी ने आगे कहा कि ऐसे

रचनाकार केवल साहित्य नहीं रचते, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। मुंबई में उनका यह सम्मान समस्त साहित्य प्रेमियों के लिए गौरव का विषय है। सरस्वती वंदना के पश्चात आयोजित काव्य पाठ में वरिष्ठ एवं युवा कवियों ने अपनी विविध रचनाओं से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने सभी रचनाकारों की सारगर्भित समीक्षा करते हुए उनके साहित्यिक योगदान की सराहना की।

अल्प समय में संपन्न यह आयोजन साहित्यिक ऊष्मा, आत्मीयता और सृजनात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। अंत में संस्था के उपसचिव आनंद पाण्डेय 'केवल' ने सभी अतिथियों, कवियों एवं श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

भुसावल मंडल द्वारा यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे द्वारा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की सुविधा केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। किन्तु हाल के समय में यह देखा गया है कि अलार्म चेन पुलिंग का उपयोग कई बार गलत एवं विभिन्न अनुचित कारणों से किया जा रहा है, जिन पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है।

इन कारणों में– गलती से चेन खींचना, यात्री का समय पर ट्रेन में चढ़ न पाना, मोबाइल फोन का नीचे गिर जाना अथवा अन्य छोटे-मोटे कारण शामिल हैं।

ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग का गलत उपयोग होने पर इसका प्रभाव केवल संबंधित ट्रेन के यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली अन्य ट्रेनों पर भी पड़ता है। एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग करने से सैकड़ों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

भुसावल मंडल ऐसी अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग घटनाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है। भुसावल मंडल में दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कुल 495 अलार्म चेन पुलिंग के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 426 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा कुल 1,43,200/- का जुर्माना वसूल किया गया है।

भुसावल मंडल की यात्रियों से अपील - मामूली कारणों से अलार्म चेन न खींचें, दूसरों को होने वाली असुविधा से बचाएँङङ

यात्रियों से अनुरोध है कि वे मामूली अथवा अनावश्यक कारणों से अलार्म

चेन न खींचें, अन्यथा इससे अन्य यात्रियों को गंभीर असुविधा हो सकती है। अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग करना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

रेलवे सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से पूर्व समय पर स्टेशन पहुँचें तथा सीमित सामान के साथ यात्रा करें। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में बैटरी चालित वाहन या व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है, जिनका उपयोग कर वे समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकते हैं और सुरक्षित रूप से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इससे मामूली कारणों से अलार्म चेन खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, वडोदरा में किया गया। बैठक के प्रारंभ में समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके द्वारा संक्षिप्त प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी सदस्यों को मंडल की गतिविधियों एवं विकास कार्यों से अवगत कराया गया। भडके ने माननीय सदस्यों को मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किये जा रहे स्टेशनों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतापनगर- जोबट क्षेत्र पर ट्रेनों की सेक्शन स्पीड बढ़ाने के साथ-साथ स्टेशनों पर प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसमें दिव्यांग फ्रेंडली सुविधा के दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि उधना स्टेशन पर यात्रियों के ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उत्राण स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा चलायी जा रही गोरखपुर एवं मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन की जानकारी भी दी। इस दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं, ट्रेनों के स्टॉपेज, विस्तार,नई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा मंडल के स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने सुझाव दिये । मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी सदस्यों के सुझावों पर शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि यात्री सुविधाओं का विकास वडोदरा मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस आयोजित बैठक में माननीय सदस्यों में सर्वश्री निपम आर देसाई, भरत आर गुप्ता, नीलेशकुमार आई पटेल, ईश्वर पी सज्जन, वंदनकुमार बी पंड्या, ओमकारनाथ तिवारी, एम. हबीब लोखंडवाला, इंद्रवदन एस जोशी, व्यास मितलभाई कौशिकभाई और राकेशचंद्र वी व्यास उपस्थित थे। बैठक के दौरान वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ईडी का अनिल अंबानी पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, मुंबई का 3716 करोड़ का घर जब्त

मुम्बई **(एजेंसी)**। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान आवास 'अबोड' पर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है, जिसकी कीमत चौंका देने वाली 3, 716.83 करोड़ रुपये है। पाली हिल के पॉश इलाके में स्थित, 66 मीटर ऊँचा और 17 मंजिला यह आलीशान टावर अब अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) में कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जब्त की गई संपत्तियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार (25 फरवरी) को हुई इस कार्रवाई की पुष्टि की, जिससे इस मामले में कुल कुर्क की गई संपत्तियों की संख्या लगभग 15, 700 करोड़ रुपये हो गई है। मुंबई के सबसे आलीशान इलाकों में से एक में स्थित 'अबोड' इमारत विलासिता का प्रतीक है, लेकिन ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान के चलते इसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। एजेंसी का आरोप है कि यह संपत्ति आरकॉम के धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेन-देन से प्राप्त धन से जुड़ी है, जो दूरसंचार कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 66 वर्षीय अनिल अंबानी से अगस्त 2025 में पीएमएलए के तहत उनकी पहली पेशी और बयान दर्ज होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जल्द ही दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। यह ऐसे समय में हो रहा है जब संघीय एजेंसी अपनी जांच को और गहरा कर रही है।

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

मंडल रेलवे प्रबंधक (पश्चिम रेलवे), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, ई-निविदा सूचना संख्याः BCT/ 25-26/323 दिनांक 20.02.2026 को आमंत्रित करता है। कार्य एवं स्थानः मुंबई सेंट्रल (मुख्य): (1) प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के प्लेटफॉर्म की सतह में दिव्यांगों के लिए उपयुक्त टाइलें, चेतावनी ब्लॉक, दोहरी ऊंचाई वाली ग्रैब रेल सहित रैंप आदि द्वारा सुधार। (2) शौचालय परिसर का निर्माण और मौजूदा सार्वजनिक शौचालयों/ शौचालयों को स्थानांतरित करना तथा असुरक्षित छत और आवरण में सुधार। (3) असुरक्षित छत की सतह में पॉलिमर प्लास्टर द्वारा सुधार और असुरक्षित आवरण को हटाना। (4) मुंबई सेंट्रल - परिचालित क्षेत्र की सतह और जल निकासी में सुधार (केवल विद्युत कार्य)। कार्य की अनुमानित लागतः 22,52,64,243.40 रुपये। ईएमडीः 12,76,300/- रुपये। जमा करने की तिथि एवं समयः 17.03.2026, दोपहर 3:00 बजे तक। खोलने की तिथि एवं समयः 17.03.2026 को दोपहर 3:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। मैन्युअल रूप से जमा किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। 1158

Like us on: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

विद्युत विद्युत कार्य

सीनियर डीईई/पी/बीसीटी, मुंबई सेंट्रल, निविदा सूचना संख्याः EL-81-937-WA-80, दिनांक 23.02.2026 को आमंत्रित करता है। कार्य और स्थानः जोरावासन सूरत खंड - एसएसई (पी वे) नवसारी के अंतर्गत पी वे डिपो के विस्तार और अन्य संबंधित कार्यों के संबंध में विद्युत (विद्युत) कार्य। कार्य की अनुमानित लागतः 23,71,255/- रुपये। ईएमडीः 47,400/- रुपये। जमा करने की तिथि और समयः 20.03.2026, दोपहर 3:00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि और समयः 20.03.2026 को दोपहर 3:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1166

Like us on : facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (सीओ), द्वितीय मंजिल, मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400008, ई-निविदा संख्याः SG-623-1814-WA दिनांक 20/02/2026 को आमंत्रित करता है। कार्य का नामः पश्चिम रेलवे, मुंबई डिवीजन के मुंबई सेंट्रल स्थित केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय में स्थापित डेल्टा कंपनी के डीएलपी आधारित रियर व्यू प्रोजेक्शन डिस्प्ले सिस्टम के लिए 3 वर्षों का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)। कार्य लागतः 95,57,044.20 रुपये। बोली सुरक्षा राशिः 1,91,200 रुपये। ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 16.03.2026, दोपहर 3:00 बजे तक। ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 16.03.2026 को दोपहर 3:30 बजे। निविदा वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 1161

Like us on: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

परामर्श सेवाओं की नियुक्ति

एसीएम (जी) बीसीटी निविदा संख्याः WRMMCTNFRCONSULTOOH2 आमंत्रित करता है। कार्य का नामः चर्चगेट और विरार के बीच स्थित आउट ऑफ होम (OOH) संपत्तियों (होर्डिंग्स, गैन्ट्री, यूनिपोल) की पहचान, मूल्यांकन और निविदा पैकेजिंग के लिए परामर्श सेवाओं की नियुक्ति। विज्ञापित मूल्यः 9,95,000/- रुपये। बयाना राशिः 19,900/- रुपये। निविदा दस्तावेज लागतः 5,000/- रुपये। निविदा प्रारंभ तिथिः 04.03.2026। निविदा समापन तिथि और समयः 18.03.2026 को दोपहर 3:00 बजे। संपर्क विवरणः लैंडलाइन नंबरः 02267644212, ईमेल आईडीः acmadvtgbct@gmail.com, कार्य समयः सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक। संभागीय कार्यालय का पताः वरिष्ठ संभागीय वाणिज्य प्रबंधक, डीआरएम कार्यालय, एनेक्सर बिल्डिंग, पहली मंजिल, वाणिज्य विभाग, एनएफआर अनुभाग, मुंबई सेंट्रल - मुंबई - 400 008। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 1157

Like us on: facebook.com/WesternRly

वन अधिकार रखने वाले आदिवासी किसान सरकार स्वतंत्र स्वामित्व अधिकार देने के लिए प्रयासरत– आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुइके

लॉन्ग मार्च आंदोलन स्थगित करने की अपील

दिव्यांश

मुंबई। सरकार आदिवासी भाइयों, किसानों, कामगारों, महिला सेविकाओं तथा स्कूल पोषण आहार कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में सकारात्मक है। कुछ मांगों पर कार्रवाई अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। वन अधिकार रखने वाले आदिवासी किसानों को अलग से स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनज़र आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुइके ने लॉन्ग मार्च आंदोलन को स्थगित करने की अपील की है।

अहिल्यानगर जिले के आदिवासी भाइयों, किसानों, कामगारों, महिला सेविकाओं तथा स्कूल पोषण आहार कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय में आदिवासी विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, विधायक विनोद निकोले, अहिल्यानगर जिला कलेक्टर पंकज एशिया, आदिवासी विकास विभाग के उप सचिव रविंद्र जाधव, संयुक्त सचिव मच्छिंद्र शेलके, किसान सभा के सचिव अजित नवले आदि उपस्थित थे। टीआरटीआई के आयुक्त चंचल पाटिल तथा अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त गोपीचंद कदम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

आदिवासी विकास मंत्री वुइके ने कहा कि वन अधिकार और सामूहिक वन पट्टे रखने वाले आदिवासी किसानों को कृषि उपज पर लागू बोनस का लाभ आदिवासी विकास महामंडल द्वारा दिया जाना चाहिए। साथ ही, महामंडल को इन आदिवासी किसानों की कृषि उपज की खरीद करनी चाहिए। एग्रीस्टैक में आदिवासी किसानों की भूमि जोत से संबंधित जानकारी आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त की जानी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर उसका अनुसरण किया जाए।

जल संसाधन मंत्री श्री विखे पाटिल ने कहा कि आदिवासी विकास महामंडल को हिरडा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए खरीद केंद्र खोला जाए। हिरडा का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाए, ताकि किसानों के साथ अन्याय न हो। अकोले तालुका के आदिवासी गांवों में नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी पहलुओं पर सर्वे किया जाएगा और सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्माण श्रमिकों की मेडिक्लेम योजना को लेकर निर्माण श्रमिकों, सूचीबद्ध अस्पतालों और प्लेसमेंट एजेंसियों के बीच जो भ्रम है, उसे दूर किया जाए। इसके लिए निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा लिखित निर्देश जारी किए जाएं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने कहा कि महिला सेविकाओं के मानधन के संबंध में मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा तथा लंबित वेतन के मुद्दे के समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि स्कूल पोषण आहार कर्मचारियों के मानधन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, किसान सभा, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, अहिल्यानगर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मेधावी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति

मुंबई। महाराष्ट्र के मेधावी विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधान भवन में महाराष्ट्र सरकार और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी मुंबई कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता ज्ञापन मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेंकटगोपाल रेड्डी, University of Bristol की कुलपति एवं अध्यक्ष प्रो. एवलिन वेल्च, मुख्य परिचालन अधिकारी लुसिंडा पार, निदेशक जूलिया हॉल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विन डामेरा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ब्रिस्टल विश्वविद्यालय जैसे विश्वप्रसिद्ध संस्थान के साथ समझौता करना गर्व की बात है। यह सहयोग महाराष्ट्र के उन विद्यार्थियों के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सरकार और शैक्षणिक संस्थान यदि साथ आएँ, तो निश्चित रूप से एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा

इस समझौते के तहत 'मुख्यमंत्री और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति योजना' को संयुक्त रूप से विकसित एवं लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना है। चयनित विद्यार्थियों को उनके संपूर्ण डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के लिए 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस माफी दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति का पूरा खर्च ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, मुंबई कैंपस द्वारा वहन किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई मध्य मंडल, पश्चिम रेलवे, वाणिज्य विभाग, एनएफआर अनुभाग, मुंबई मध्य, मुंबई - 400008

कार्य - मुंबई मंडल में विभिन्न एनएफआर माध्यमों से विज्ञापन प्रदर्शित करना।

नीलामी सूची क्रमांक	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-PnU-25-19	16-03-26 14:00:00

क्रम संख्या	लॉट संख्या	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	PnU-BCT-MMCT-WRL-80-25-1 (भुगतान और उपयोग - लाउंज/प्रतीक्षा कक्ष/ विश्राम कक्ष/क्लोकरूम)	मुंबई सेंट्रल (MMCT) स्टेशन पर विश्राम कक्ष/डॉरमेट्री के नवीनीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए ई-नीलामी	1826	16-03-26 14:30:00

नीलामी सूची क्रमांक	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-81	16-03-26 15:00:00

क्रम संख्या	लॉट संख्या	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	ADVT-Int-S1-EMU15car-357- 26-1 (विज्ञापन - ट्रेन का आंतरिक भाग)	पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन में चलने वाली 15 डिब्बों/कोचों वाली 10 EMUS ट्रेनों में 5 वर्षों की अवधि के लिए आंतरिक पैनलों और रूट मैप के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करना।	1826	16-03-26 15:30:00

संपर्क विवरणः लैंडलाइन नंबरः 02267644212. ईमेल आईडीः acmadvtgbct@gmail.com नोटः इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। वहां उल्लिखित कैटलॉग के अंतर्गत लॉट-वार विवरण उपलब्ध हैं। 1170

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान

'मदरसों को बंद करो, इनमें पलते हैं आतंकी'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बुधवार को मदरसों को आतंकवादियों के लिए पनपने की जगह करार दिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में इस्लामी स्कूलों को बंद करने का आग्रह करेंगे। विधानसभा भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने हमले को और तीखा बनाने के लिए एक वायरल वीडियो का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर एक मौलवी एक छात्र को पीटते हुए दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा, 'आपने बच्चों को पीटते हुए मौलवी का वीडियो देखा है। यह सावंतवाड़ी का है, जो मेरा गृह जिला है और मैं जिले का पालक मंत्री भी हूं। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होने वाली है।' राणे सिद्धुदुर्ग जिले के कंकावली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

'मदरसों की जरूरत ही क्यों है' : नितेश राणे

नितेश राणे ने कहा, 'मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार बच्चों के साथ ऐसा करने से पहले उनके हाथ कांप उठेंगे।' भाजपा नेता ने मदरसों की जरूरत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'मदरसों की जरूरत ही क्यों है? यही मूल प्रश्न है। ये मदरसे आतंकवाद के गढ़ हैं। यहीं पर आतंकवादी तैयार होते हैं।'

राणे ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई इस्लामी देश हिंदुओं के लिए ऐसे स्कूलों की अनुमति देता है, जहां केवल भगवद गीता पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा, 'हमें ऐसे मदरसों को क्यों बढ़ावा देना चाहिए? अगर आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मस्जिदें हैं। कभी-कभी इन मदरसों में हथियार मिलते हैं, और कभी-कभी बच्चों की पिटाई जैसी घटनाएं भी होती हैं।'

राणे के बयान पर क्या बोले अबू आजमी?

मंत्री ने कहा कि इस्लामिक स्कूल को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया, 'मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनसे सभी मदरसों को बंद करने के लिए कहूंगा, क्योंकि यहां आतंकवादी पैदा होते हैं।' इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत के किसी भी मदरसे में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती है।

अबू आजमी ने कहा, 'अगर वे चाहें तो मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। उन्हें रहने के लिए कमरा और खाना दिया जाएगा। वे वहां रहकर जांच कर सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ऐसी कोई गतिविधि नहीं मिलेगी।'

आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर सकारात्मक- महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य की आंगनवाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है तथा आंगनवाड़ी कर्मियों का योगदान सराहनीय है, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा। मंत्रालय में आयोजित बैठक में महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी कृती समिति तथा संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. अनुकुमार यादव, आयुक्त कैलाश पगारे, संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्ष माया परमेश्वर, कृती समिति की अध्यक्ष शुभा शमीम, कर्मचारी संघ के संगठन सचिव राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों का कार्य 100 प्रतिशत ईमानदार और समर्पित है। उन्होंने प्रोत्साहन भत्ते से संबंधित तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे मुद्दों पर अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाएगा। पोषण ट्रैकर में नवीनतम जानकारी का नियमित अद्यतन करने से कार्य अधिक प्रभावी होगा। विभाग के माध्यम से तकनीकी समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है और उनके हित में निर्णय लेने का प्रयास कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा।

बैठक में प्रोत्साहन भत्ते को मानधन में परिवर्तित करना, ग्रेच्युटी और पेंशन, बीमारी के दौरान पूर्ण वेतन सहित अवकाश, आंगनवाड़ी केंद्रों में मासिक टीएचआर कोटा, 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन' योजना के अंतर्गत प्रपत्र भरने के लिए प्रोत्साहन भत्ता, सहायिकाओं से सेविका पद पर पदोन्नत कर्मियों एवं मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों की आयु सीमा, योजना कार्य के लिए हर स्थान पर मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता तथा अनुपूरक पोषण आहार की गुणवत्ता में सुधार जैसे विषयों पर सकारात्मक चर्चा की गई।

राज्यपाल का अभिभाषण 'झूठे आंकड़ों का पुलिंदा': महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार पर बरसे विजय वडेट्टीवार

मुंबई। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को पुरानी बातों का दोहराव और शब्दों का बाजार बताया। वडेट्टीवार ने कहा कि यह भाषण पूरी तरह से निराशाजनक है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए वडेट्टीवार ने महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यपाल को सदन के सामने खुला झूठ पेश करने के लिए मजबूर किया। यह महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है।

महापुरुषों का अपमान करने का आरोप

वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार राजनीतिक दिखावे के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉ. बी.आर. आंबेडकर का नाम लेती है। लेकिन अपने कामों से लगातार उनकी विचारधाराओं का अपमान करती है। उन्होंने कहा, 'इस सरकार ने उन लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने राजभवन में बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था।' उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. आंबेडकर ने सभी को समानता से जीने का अधिकार दिया, लेकिन आज के मंत्री सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले बयान दे रहे हैं।

अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने सरकार के आर्थिक अनुमानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले 2024 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का वादा कर रही थी। अब वे उस वादे को भूलकर 2047 के विजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, 'वे 1 ट्रिलियन डॉलर का वादा भूल गए हैं और अब 5 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। क्या मौजूदा लक्ष्यों के परिणाम दिखाए बिना 2047 के बारे में बात करना सही है?' उन्होंने इन आंकड़ों को महज हवाई बातें बताया।

'कमीशन' वाली सरकार के गंभीर आरोप

वडेट्टीवार ने शिक्षा की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 2,200 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और मराठी माध्यम के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार एंबुलेंस की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रही है, लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर की बातें करती है।

उन्होंने सरकार पर 'कमीशन' के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि स्कूल बैग के ठेके पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दवा कंपनियों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर ताडोबा टाइगर रिजर्व और नागपुर वन प्रभाग की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने का भी आरोप लगाया। वडेट्टीवार ने किसानों के संकट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यवतमाल और अमरावती में किसान कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने को मजबूर हैं, लेकिन राज्यपाल के भाषण में 'कर्जमुक्ति' का कोई जिक्र नहीं था।

उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर हुए समझौतों को 'बढ़े-चढ़े आंकड़े' बताया। उन्होंने सवाल किया कि भारतीय और महाराष्ट्र की कंपनियों के साथ समझौते करने के लिए दावोस जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने इन विदेश यात्राओं से मिले असल रोजगार पर एक श्वेत पत्र की मांग की।

डीजल खरीद में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ;निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की डीजल खरीद से संबंधित निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा, ऐसी सख्त चेतावनी परिवहन मंत्री तथा महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां मीडिया में भ्रामक समाचार फैलाकर निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।

मंत्री सरनाईक ने बताया कि वर्तमान में महामंडल को प्रतिदिन औसतन 10 लाख 87 हजार लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। यह डीजल मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से खरीदा जाता है।

थोक ग्राहक होने के कारण महामंडल को प्रति लीटर रू 2.70 की छूट दी जाती थी। संबंधित कंपनी के साथ हुई बैठक के बाद इस छूट में रू 30 पैसे की वृद्धि की गई। इसके परिणामस्वरूप महामंडल को प्रतिवर्ष लगभग रू 10 से 12 करोड़ की बचत होने लगी। हालांकि रू 3 की छूट मिलने के बावजूद किए गए अध्ययन में यह सामने आया है कि अन्य राज्यों के परिवहन महामंडलों को इससे अधिक छूट मिल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन महामंडलों को 4 से अधिक की छूट दी जा रही है, जबकि

आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडल को रू 5.50 की छूट मिल रही है।

अन्य राज्यों में लागू प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया को इसका मुख्य कारण बताते हुए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने भी डीजल खरीद के लिए उसी तर्ज पर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए एक कंपनी ने न्यायालय का रुख किया था, लेकिन न्यायालय ने निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि संबंधित कंपनियों को समय बर्बाद करने और मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाकर निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के निरर्थक प्रयास बंद करने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजल खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमितता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

वर्तमान में महामंडल पर लगभग रू 12,000 करोड़ का कुल संचयी घाटा है। प्रतिवर्ष लगभग रू 3,400 करोड़ डीजल खरीद पर खर्च होते हैं। निकट भविष्य में बेड़े में 8,000 नई डीजल बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यह खर्च बढ़कर लगभग रू 4,700 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में यदि डीजल की कीमत में केवल 1 की भी कमी हो जाए, तो प्रतिवर्ष लगभग रू 50 से 55 करोड़ की बचत संभव है, जो महामंडल के लिए बड़ी वित्तीय राहत साबित होगी।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि महामंडल की वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निविदा प्रक्रिया नियमों के अनुसार, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी तथा महामंडल के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र में सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव: 5 मार्च तक नामांकन, 16 मार्च को होगा मतदान;

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि राज्य से सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। सदस्यों के चुनाव के लिए 16 मार्च को होगा। इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर विलास अठवाले ने दी। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। इसके बाद 6 मार्च को नामांकनों की जांच (स्क्रूटनी) होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य इस चुनाव में मतदान करेंगे। राज्य से सात राज्यसभा सांसदों की अवधि अप्रैल में समाप्त हो रही है, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल हैं। अभी तक पवार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे पुनः उम्मीदवार होंगे या नहीं। ऐसे में यदि आवश्यकता हुई, तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधान भवन में मतदान होगा और उसके बाद मतगणना की जाएगी।

राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है?

राज्यसभा के सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं, जिस राज्य से वह

उम्मीदवार है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इस सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है।

राज्यसभा चुनावों के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है।

जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के फॉर्मूला के हिसाब से यहां किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए कम से कम 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के मुताबिक सत्ताधारी गठबंधन सात में छह सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकता है। विपक्ष एकजुट नहीं होता तो सातवें उम्मीदवार के लिए मुकाबला रोचक हो सकता है।

राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में मिलकर काम करने का संकल्प लिया

भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 27 वर्षों के बाद आयोजित किया गया था और इसमें 30 राज्यों के राज्य चुनाव आयोगों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे।

सम्मेलन में राज्य चुनाव आयुक्तों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे सफल बताया। सभी ने हर साल ऐसे राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सभी ने राष्ट्रीय घोषणा 2026 को अपनाया। घोषणा में जोर दिया गया कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना लोकतंत्र की मजबूत नींव है और चुनावों का पारदर्शी तथा सुचारू संचालन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाता है।

'हिंद-दी-चादर' कार्यक्रम स्थल पर नवी मुंबई और पनवेल महानगरपालिका आयुक्तों द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

देश-विदेश से लगभग 18 से 20 लाख नागरिकों के 350वें 'हिंद-दी-चादर' शहीदी समारोह में शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, 28th February और 1st March को ओवे मैदान, सेक्टर 29, खारघर में आयोजित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी के कार्यक्रम हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोंकण संभागीय आयुक्तालय के नियंत्रण में व्यापक और उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यद्यपि यह कार्यक्रम पनवेल महानगरपालिका की सीमा में आयोजित हो रहा है, फिर भी पड़ोसी महानगरपालिका होने के नाते नवी मुंबई महानगरपालिका संपूर्ण सहयोग के साथ आयोजन कार्य में सहभागी है।

नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष कार्यक्रम स्थल का दौरा कर संपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ पनवेल महानगरपालिका आयुक्त श्री मंगेश चिटाले, नवी मुंबई महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार, शहर अभियंता श्री शिरीष आर्डवाड, अतिरिक्त शहर अभियंता श्री अरविंद शिंदे, प्रशासन विभाग के उपायुक्त श्री किसानराव पलांडे, जोन 1 के उपायुक्त श्री सोमनाथ पोत्रे, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जावड़े, घन कचरा प्रबंधन उपायुक्त डॉ. अजय गडे, परिवहन उपक्रम के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी श्री तुषार दौंडकर सहित नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिकाओं के अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा रायगढ़ के उपजिलाधिकारी (रोहयो) तथा 'हिंद-दी-चादर' कार्यक्रम के समन्वयक श्री रविंद्र राठोड़ और श्री हैप्पी सिंह भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्य मंच का निरीक्षण किया गया। पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, लंगर व्यवस्था, खाद्यान्न एवं सामग्री भंडारण व्यवस्था, सभा व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था तथा हेलिपैड व्यवस्था जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए आईसीयू, कार्डियक एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार तथा दवाओं की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वातावरण में गर्मी को देखते हुए पीने के पानी, ओआरएस, जूस आदि की अधिकतम व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। इसी प्रकार परिसर की स्वच्छता और शौचालयों की साफ-सफाई पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई।

लंगर व्यवस्था के पास आज से ही अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चूंकि इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में नागरिक आएंगे, इसलिए यातायात नियोजन को सुव्यवस्थित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पनवेल महानगरपालिका द्वारा यह जानकारी देने के लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है कि कौन-से वाहन कहां पार्क किए जाएंगे, और इस जानकारी का अधिकतम प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी इस अवसर पर दिए गए।

कार्यक्रम के लिए आवास, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा, शौचालय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यात्री परिवहन व्यवस्था और दैनिक स्वच्छता जैसी सभी आवश्यक सेवाओं में सहायता प्रदान करने में नवी मुंबई महानगरपालिका अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसके साथ-साथ नवी मुंबई के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों और संगठनों के माध्यम से व्यापक जनजागरण किया जा रहा है। 10th February से डिजिटल माध्यमों, फ्लेक्स होर्डिंग्स, बसों व बस स्टॉप पर होर्डिंग्स, सिनेमा हॉल में भक्ति गीतों का प्रसारण, स्कूल-महाविद्यालयों में वृत्तचित्रों का प्रदर्शन तथा सभी सोशल मीडिया माध्यमों से कार्यक्रम की जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रातःकालीन फेरी, निबंध, चित्रकला और वक्तृत्व जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।

राज्य को काजू उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम

अत्याधुनिक स्वचालित काजू प्रक्रिया उद्योग की स्थापना- विपणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई। राज्य में काजू उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके लिए काजू बागवानी क्षेत्र बढ़ाने से लेकर बिक्री तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करनी होगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, भंडारण क्षमता विकसित करने, काजू उत्पादन से बिक्री तक मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने, तथा वियतनाम और कंबोडिया की तर्ज पर राज्य में अत्याधुनिक स्वचालित काजू प्रक्रिया उद्योग स्थापित करने और काजू उत्पादन बढ़ाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की योजना तैयार करने जैसे सुझाव राज्य के विपणन मंत्री एवं महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद के अध्यक्ष जयकुमार रावल ने दिए। वे राज्य काजू परिषद के संचालक मंडल की बैठक में बोल रहे थे। महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद के संचालक मंडल की बैठक मुंबई स्थित सह्याद्री राज्य अतिथिगृह में परिषद के अध्यक्ष एवं विपणन मंत्री जयकुमार रावल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य विपणन महासंघ के कार्यकारी संचालक राहुल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, विपणन विभाग के संयुक्त सचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल के महाव्यवस्थापक विनायक कोकरे, एपीडा के उपमहाव्यवस्थापक वाघमारे सहित शासन नियुक्त तज्ज्ञ संचालक मनीष दलवी, डॉ. परशुराम पाटील, धनंजय यादव, रूपेश बेलोसे उपस्थित थे।

मंत्री रावल ने कहा कि राज्य में काजू उत्पादन की क्षमता अच्छी होने के बावजूद प्रक्रिया के लिए काजू का आयात करना पड़ता है। इसलिए आने वाले वर्षों में राज्य में काजू उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए काजू उत्पादकों को काजू बागवानी क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उत्पादन क्षेत्रों में भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु आधारभूत संरचना विकसित करने की योजना बनाई जाए।

सम्पादकीय

भारत-ब्राजील समझौता ड्रैगन के एकाधिकार को चुनौती और ग्लोबल साउथ का सुनहरा उदय

मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू-राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खासतौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके मद्देनजर अलग-अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं, विकल्प की राह खोजी जा रही है।

भारत और ब्राजील के बीच हुए समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ते तैयार हों। आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति शृंखला बनाई जाए। भारत-ब्राजील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस समझौते में अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डालर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू-धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं। इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लीथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ खनिज तथा भू-धातु विकास के संचालक तत्त्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफी तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। भारत-ब्राजील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि ब्राजील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राजील के साथ नए करार के बाद भारत को इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लेकर एक सहमति बनी है। इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ-साथ ब्राजील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है, तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है।स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

बांग्लादेश की नई सरकार में हिंदू मंत्रियों की आमद

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान के रूप में नई सरकार शपथ ले चुकी है। खास बात ये है रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में दो हिंदू सांसदों को मंत्री बनाया गया है। उनके इस निर्णय को भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में समूची दुनिया देख रही है। इस कदम से चीन-पाकिस्तान चिड़े भी हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश भारत या उनसे वास्ता रखने लोगों को तवज्जो दे। लेकिन, तारिक रहमान ने उनके नापाक मंसूबों को धता बताते हुए, बड़ी सूझबूझता से कदम आगे बढ़ाया। बीते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई, बल्कि दशको से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्खियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तो की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्वारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है।

गौरतलब है कि तारिक रहमान के आगाज से पूर्व बांग्ला-हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए हैं और हो भी रहे हैं? ऐसी निंदनीय घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने की चुनौती रहा था। रहमान अच्छे से समझते हैं कि जबतक मोहम्मद यूनुस कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की हर संभव कोशिशें कीं। कुछ

तारिक रहमान के सामने अभी भी खड़ी है। हालांकि, रोकने के लिए वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री रहमान सबसे पहले पूर्व की अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के अटपटे और संबंध बिच्छेद भरे निर्णयों की समीक्षा करेंगे। उनका झुकाव भारत को परेशान करने वाली पाकिस्तान-चीन की संयुक्त खुराफाती नीतियों की ओर ज्यादा उन्होंने की और कुछ दूसरे देशों ने करवाई? दूसरे देश कौन से हैं जिनके नाम लेने की शायद जरूरत नहीं? सभी जानते हैं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारतीय हुकूमत का साथ लेकर और अपनी कैबिनेट में अल्पसंख्यक हिंदू मंत्रियों की आमद के साथ बांग्लादेश में अगले पांच सालों तक समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जब उनकी पार्टी बीएनपी चुनावों में जीती तो सबसे पहले वह अपने धुरविरोधी विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान के बिना बुलाए, ढ़लती शाम के बाद उनके आवास पहुंच गए। चुनावी गुस्सेबाजियों के इतर उनसे नई सरकार में सहयोग की गुजारिश करी। विपक्षी नेता ने भी राजनीतिक दुश्मनी छोड़कर उनका गर्मजोशी से अपने घर पर स्वागत किया। दरअसल, इस तरह की खूबसूरत परंपरा का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, कि चुनाव बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये उन देशों के लिए सीख भी है जहां पक्ष-विपक्ष आपस में अनैतिक कुकर्मों की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। रहमान उस विपक्षी नेता के घर भी पहुंचे जिनकी पार्टी चुनावों में तीसरे स्थान पर रही। नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम को भी गले लगाया और बांग्लादेश के विकास में उनसे भी सहयोग मांगा। राजनीति में ऐसी तस्वीरों का दिखना दुर्लभ होता है, लेकिन बांग्लादेश में दिखी।

रहमान की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्हें भाई बताना और उनकी जीत की खुशी में फूल-मिठाईयां को ढाका भेजना भी धूमिल संबंधों में रस भरने जैसा कहा जाएगा। साथ ही रहमान के शपथ में भारत सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पहुंचना भी सुखद और नए संबंधों में नए सिरे से गढ़ने जैसा है। नए रंग में रिश्तों को रंगने की दरकार इसलिए भी महसूस होने लगी है क्योंकि बांग्लादेश की सत्यानाशी के लिए जिस तरह से चीन-पाकिस्तान मिलकर घेराबंदी कर रहे हैं जिसका अंदाजा नवगठित सरकार के मुखिया को भी है।

बांग्ला-हिंदू संबंध जितने बिगड़ेंगे, उतना फायदा ये दोनों मुल्क मिलकर उठाएंगे। पूर्व की कार्यकारी सरकार को इन्होंने कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के सह पर बांगाली और हिंदुओं को खूब लड़ाया गया। लेकिन संपन्न हुए 13वें राष्ट्रीय चुनाव में तीन हिंदू समुदाय के सांसद जीते हैं जिनमें निताई रॉय चैधरी को स्पीकर, चंटगांव से जीते अधिवक्ता दीपेन दीवान को पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए मंत्री, तो वहीं गोयेश्वर रॉय चैधरी को महत्पूर्ण रेलमंत्री बनाया गया है।

बांग्लादेश में नवगठित हुकूमत के साथ करीब एक डेढ़-सालों से दंगों का दंश झेल रहे देश में आखिरकार नई सुबह का आगाज हो चुका है। आवाम को इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। वहां काफी जद्दोजहद और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुए आम चुनावों में बीएनपी ने बड़े मार्जिन से विजय हासिल की है। कुल संसदीय 298 सीटों में 297 पर चुनाव हुए, उनमें से रिकॉर्ड 209 सीटें बीएनपी ने जीतीं। दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी पार्टी रही जिसने 68 सीटें जीतीं। तारिक रहमान की नई कैबिनेट में डॉ. खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, सलाहुद्दीन अहमद को गृह मंत्री, डॉ. अमीर खसरू महमूद को वित्त एवं प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर तारिक रहमान ने शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों से अपनी कैबिनेट को सजाया हैं। कैबिनेट में कुल 50 मंत्री हैं जिनमें 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं।

क्या हम सिर्फ अतीत का दोहराव जी रहे हैं?

समय एक-सा नहीं रहता। बदलता रहता है। मान्यता है कि समय की स्लेट पर इतिहास लिखे जाते हैं। जीवन में लिखे का बड़ा महत्त्व होता है, क्योंकि लिखे को बदलना आसान नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। समय के चक्र में दोहराव चलता रहता है। यही दोहराव जब बार-बार होने लगे, तब नया रुक जाता है। नए की आवक अवरुद्ध हो जाती है और नए को नया मानना बेहद कठिन हो जाता है।

हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, इसके विस्तार में जाएं, तो वह सब पुराना है। चिंतकों का तर्क है कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, वह सब पुराना है। नया कुछ भी नहीं। यहां तक कि व्यक्ति की सोच भी नई नहीं है। दरअसल, नई सोच का आना लगभग असंभव हो गया है। व्यक्ति जो भी सोच रहा होता है, वह महज दोहराव रह गया है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की कुल सोच में दोहराव की मात्रा सबसे अधिक होती है। व्यक्ति बार-बार वही सोचता है जो उसने पूर्व में सुना या देखा होता है।

बचपन से लेकर आज तक जो सीखा या सिखाया जाता है, उसी का दोहराव अंदर चलता रहता है। उठते-बैठते, सोते-जागते मन में विचारों के दोहराव का क्रमचय-संचय चलता रहता है। इनमें से कुछ विचारों के संचय को नई सोच का निर्धारण मान लिया जाता है। फिर सवाल उठता है कि व्यक्ति के शैशव काल में जो सिखाया जाता है वह तो नया ही होता है! सच यह है कि बच्चों को सिखाने वाला भी वही सिखाता है, जो उसने पूर्व में सीखा हुआ होता है। धरती की उत्पत्ति के बाद से सोच का करोड़ों-करोड़ों बार दोहराव होता आया है। होता रहेगा। सोच और विचारों की पुनरुक्ति चाहे-अनचाहे होती रहती है। इसलिए आज के समय की विडंबना है कि नयापन रुक गया है। पुनरुक्ति से नयापन लगभग समाप्त हो रहा है। दृश्य और श्रव्य के इलेक्ट्रानिक साधन ये काम बखूबी कर रहे हैं। सोशल मीडिया दोहराव के मंच हैं। इसलिए दोहराव आसान है और नई सोच का निर्माण कठिन। जो दोहराव से बच गया, वह अमर हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग विरले हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं, वही दूर बैठा हमारा साथी भी सोच रहा होता है। जब हम यह बात अपने साथी को बताते हैं, तब वह आश्चर्य में पड़ जाता है। बोलता है कि वह भी तो वही सोच रहा था!

ऐसे मामले हमारी दिनचर्या के हिस्से हैं। ऐसे मामलों में और गहराई से विचार किया जाए, तब कोई और भी कह सकता है कि ऐसा तो वह पहले ही सोच चुका है। दरअसल, यह दायरे में सोच और दोहराव का परिणाम है। आज यह अधिक हो रहा है। सोचने वालों की संख्या बढ़ गई है इसलिए दोहराव भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है।

विज्ञान मानता है कि आधुनिक विमानों का आविष्कार नई सोच के परिणाम हैं। आगे भी परिष्कृत निर्माण होते रहेंगे। विमान पायलट रहित हो जाएं इसकी प्रबल संभावना है। जैसे अंतरिक्ष यान पूरी तरह स्वचालित हैं।

पौराणिक उल्लेख इस सोच के बरक्स दोहराव की दलील को मजबूत करते हैं। 'रामायण' में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख है। इसे क्या कहेंगे? पुष्पक विमान न केवल आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था, बल्कि व्यक्ति की सोच से उड़ता था। सबसे नई तकनीक से लैस आधुनिक टीवी का आविष्कार भी विज्ञान की नई सोच का सिर्फ उदाहरण है। महाभारत में युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाए जाने का प्रसंग क्या था? इसे कल्पना और यथार्थ या फिर कल्पना से यथार्थ के सफर के तौर पर देखा जा सकता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर हिंदी सहित तमाम दुनिया के संगीत पर पड़ताल जारी है।

यहां यह जानकर अचंभित हो जाना पड़ता है कि जिन खूबसूरत फिल्मी गीतों को हम धरोहर मानते हैं, जिनकी मिठास हमें झंकृत कर जाती है और जिन गीतों को सुनकर हमें गर्व होता है, उनका संगीत दोहराव का परिणाम है। न केवल यह, बल्कि यह भी कि जिस संगीत को हम दोहराव मान रहे हैं, वह भी दोहराव का परिणाम है। फिर सवाल उठता है कि संगीत का मूल स्रोत कहां है? यह पड़ताल और भी गहराई में उतर सकती है। संगीत की किसी धुन की मौलिकता पर प्रश्न नहीं है, लेकिन दोहराव का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ? क्या यह क्रमशः विस्तार है? हाल ही में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता पर एक ताजा शोध पत्र जारी हुआ। शोध में यह जानने की कोशिश की गई है कि लगभग दस हजार साल पुरानी दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता समाप्त कैसे हुई। कहां गए वे लोग, जिन्होंने इस विकसित सभ्यता का निर्माण किया? इस सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि यहां अति-विकसित बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थीं। मल निस्तारण के लिए फ्लश शौचालय बनाए जाते थे। सीवर लाइनें थीं। इस तरह से आज की अधुनातन ऊंची इमारतें, विकसित कालोनियां और फ्लश शौचालय उस सभ्यता का दोहराव मात्र नहीं हैं? फिर सवाल उठता है कि सर्वथा नया कहां है? पुराने से मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या दोहराव से बचा जा सकता है? सोच के दोहराव से बचने के लिए सोच को रोकना होगा। सोच के निर्वात में जो विचार पैदा होगा क्या वह नया होगा? क्या यह संभव है?

शिक्षा की कसौटी या सामाजिक प्रतिष्ठा का युद्ध?

हर वर्ष फरवरी और मार्च का महीना आते ही देश के लाखों घरों में एक अलग-सी गंभीरता उतर आती है। पढ़ाई की मेज पर किताबों का ढेर बढ़ जाता है, दीवारों पर चिपके परीक्षा कार्यक्रम घर की दिनचर्या तय करने लगते हैं और बातचीत का केंद्र एक ही विषय रह जाता है- बोर्ड परीक्षा। दसवीं और बारहवीं की ये परीक्षाएं हर साल आती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ा तनाव और सामाजिक दबाव भी लगभग उतनी ही नियमितता से लौटता है।

दरअसल, यह सिर्फ विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होती, यह परिवारों, विद्यालयों और पूरे सामाजिक परिवेश की मानसिकता की भी परीक्षा होती है।

हमारी शिक्षा संस्कृति में बोर्ड परीक्षाओं को एक निर्णायक मोड़ की तरह देखने की परंपरा रही है। परिणाम आते ही फीसद के आधार पर बच्चों की क्षमता और पहचान तय कर दी जाती है। कुछ अंक ऊपर-नीचे होते ही किसी को मेधावी, किसी को औसत और किसी को कमजोर मान लिया जाता है।

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बच्चों के मन में यह धारणा बना देती है कि उनका पूरा भविष्य कुछ अंकों पर टिका हुआ है। यहीं से परीक्षा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया न रहकर सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। किशोरावस्था का समय अपने आप में संवेदनशील होता है। यही वह दौर है, जब बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान रहे होते हैं और आत्मविश्वास विकसित कर रहे होते हैं। ऐसे समय में बोर्ड परीक्षा उनके सामने पहली बड़ी सार्वजनिक चुनौती बनकर आती है।

परिणाम केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज की चर्चा का विषय बन जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में चिंता और दबाव बढ़ता है, और कई बार यह दबाव पढ़ाई से अधिक उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। यहां एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या कुछ घंटों की परीक्षा में मिले अंक किसी विद्यार्थी की पूरी योग्यता तय कर सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक जुटाना नहीं, बल्कि समझ, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना है, लेकिन जब पूरी चर्चा अंकों तक सिमट जाती है, तो सीखने की प्रक्रिया पीछे छूट जाती है और प्रतिस्पर्धा आगे आ जाती है।

नई शिक्षा नीति बहुआयामी मूल्यांकन, कौशल आधारित शिक्षा और सतत आकलन की बात करती है, लेकिन सामाजिक व्यवहार अब भी अंकों को ही अंतिम सत्य मानने का आदी है। यह विरोधाभास ही परीक्षा के आसपास अनावश्यक दबाव पैदा करता है। परीक्षा के समय बच्चों पर इस दबाव का असर साफ दिखाई देता है। उनकी नींद कम हो जाती है, दिनचर्या असंतुलित हो जाती है और आत्मविश्वास की जगह चिंता ले लेती है। कई बार मेहनती छात्र भी परीक्षा कक्ष में अपने ही डर से हार जाते हैं। इस डर से किसी बच्चे का आत्महत्या कर लेना बेहद त्रासद है। यह स्थिति बताती है कि समस्या पढ़ाई की कमी नहीं, बल्कि दबाव की अधिकता है।

जब मन आशंकाओं से भरा होता है, तो याद की हुई बातें भी स्पष्ट नहीं रह पातीं। इसीलिए तैयारी का अर्थ केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखना भी है। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे समय में बच्चों के लिए संतुलित तैयारी सबसे जरूरी होती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, हल्की शारीरिक गतिविधि और समझ के साथ की गई पढ़ाई- ये सभी बातें उनकी क्षमता को बेहतर बनाती हैं। बिना रुके घंटों पढ़ना हमेशा बेहतर परिणाम नहीं देता, बल्कि संतुलित और समझ पर आधारित तैयारी ही आत्मविश्वास पैदा करती है।

परीक्षा के दिनों में यह समझना जरूरी है कि शरीर और मन दोनों को साथ लेकर चलना ही असली तैयारी है। परीक्षा के नजदीक आने पर दबाव में आकर की गई पढ़ाई के नतीजे ज्यादा ठोस और सार्थक नहीं निकलते। इससे संभव है कि विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक के स्तर पर जो मजबूती आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती। इस दौर में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अधिकांश माता-पिता बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन कई बार यही चिंता दबाव में बदल जाती है। तुलना, अपेक्षाओं की लगातार चर्चा या परिणाम को लेकर डराने वाली बातें बच्चों के मन में असुरक्षा पैदा करती हैं। इसके विपरीत, घर का शांत वातावरण, भरोसे से भरी बातचीत और नियमित दिनचर्या बच्चों को मानसिक स्थिरता देती है। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं तय होगा, तो वे अधिक सहज होकर अपनी तैयारी पर ध्यान दे पाते हैं। शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।

स्कूलों की रैंकिंग, सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की सूचियां और फीसद आधारित प्रतिष्ठा की होड़ कई बार बच्चों को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में धकेल देती है। शिक्षा का उद्देश्य जहां समझ और आलोचनात्मक विवेक विकसित करना होना चाहिए, वहां परिणाम संस्थानों की साख का पैमाना बन जाता है। अगर विद्यालय परीक्षा को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर चलें और काउंसलिंग, संवाद तथा समय प्रबंधन पर ध्यान दें, तो दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ऐसे समय में शिक्षक केवल विषय पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शक बन जाते हैं। एक शिक्षक का संतुलित व्यवहार, परीक्षा से पहले दिए गए व्यावहारिक सुझाव या एक भरोसा दिलाने वाला वाक्य- ये सब बच्चों के मनोबल को मजबूत करते हैं। कई विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की एक सकारात्मक टिप्पणी ही परीक्षा के दबाव के बीच सहारा बन जाती है।

इस संबंध में समाज और मीडिया में जो उत्तेजना देखी जाती है, उसके मद्देनजर इनकी भूमिका पर भी विचार आवश्यक है। परिणाम आते ही सुर्खियां सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के इर्द-गिर्द घूमने लगती हैं। यह प्रेरक हो सकता है, लेकिन जब पूरी चर्चा उसी तक सीमित रह जाती है, तो एक संदेश फैलता है कि सफलता का एक ही पैमाना है- अधिकतम अंक। यह दृष्टिकोण न तो वास्तविक है और न उपयोगी। जीवन के रास्ते केवल बोर्ड परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होते।

आज का शैक्षिक और व्यावसायिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक डिग्रियों के साथ-साथ कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी क्षेत्रों, रचनात्मक पेशों और उद्यमिता के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा को जीवन का अंतिम निर्णय मान लेना यथार्थ से दूर की सोच है। अच्छे अंक अवसरों के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन कम अंक जीवन के रास्ते बंद नहीं करते। दरअसल, बोर्ड परीक्षा को एक ऐसे पड़ाव की तरह देखना चाहिए, जो बच्चों को अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है।

यह जीवन की लंबी यात्रा का एक चरण है, मंजिल नहीं। जब समाज इस सरल सत्य को स्वीकार करेगा, तब परीक्षा के आसपास का दबाव कम होने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में तीनों पक्ष- बच्चे, अभिभावक और शिक्षण संस्थान- एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बच्चों को मेहनत और समझ के साथ तैयारी करनी है, अभिभावकों को भरोसे का वातावरण बनाना है और स्कूलों को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है। जब यह संतुलन बनता है, तभी परीक्षा एक स्वस्थ अनुभव बनती है।

हर साल बोर्ड परीक्षाएं होंगी, परिणाम आएंगे और नई पीढ़ियां इस प्रक्रिया से गुजरती रहेंगी, लेकिन किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता अंकों की सूची से नहीं, बल्कि उन बच्चों के आत्मविश्वास से तय होती है, जो परीक्षा के बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर परीक्षा उन्हें संतुलन, मेहनत और विश्वास सिखाती है, तो वही उसकी असली सार्थकता है। और अगर वह उन्हें डर, तुलना और असुरक्षा में उलझा देती है, तो समस्या अंकों में नहीं, हमारी सोच में है।

बालीपुर ग्राम सभा में एक गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ गांव में छाया सन्नाटा

थरवई। धर्मेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय इंद्रजीत सरोज रात अपनी छोटी पुत्री के लिए सिकंदरा दवा के लिए जा रहे थे अचानक सिकंदरा पुल के पहले पहुंचते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे यथा स्थान पर 108 पहुंची और घायल धर्मेंद्र कुमार को अस्पताल ले जाया गया लेकिन गरीब परिवार पूरी तरीके से अपना खेत घर बेचकर इलाज करवाया लेकिन परंतु इलाज के दौरान धर्मेंद्र का देहांत हो जाता है जिस घर परिवार को चलाने वाले इकलौते बड़े पुत्र थे और बचपन में ही उनके माता-पिता का भी देहांत हो गया था दुखों में इनका पालन पोषण हुआ और मा जब परिवार की स्थिति संभालने की बारी आई तो इनका अचानक दुर्घटना हो जाता है और इनकी शादी महज 5 वर्ष हुई थी जिससे उनके तीन छोटे-छोटे दो बच्चियों एक बच्चा भी है और सामाजिक धार्मिक विचार के व्यक्ति थे यह दुर्गा पूजा में पंडा के रूप में नवरात्रि में मां दुर्गा की सेवा पूजा अर्चना करते थे परंतु ऐसा दुखों का पहाड़ टूट इस परिवार पर की गांव में सन्नाट छाया हुआ।

उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, देगे मुंहतोड जवाब सनातन हुंकार रैली' में शामिल हुए हजारों सनातनी

जय माँ भवानी' से गूँजा प्रयागराज, उमड़ा भारी जन-समुदाय

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। हनुमत संग प्रयागराज का हृदय स्थल सिविल लाइंस आज उस समय राष्ट्रवाद और सनातन के जयघोष से गुंजायमान हो उठा, जब हनुमत संग के गौरवशाली नेतृत्व में आयोजित 'सनातन हुंकार रैली' में हजारों की संख्या में सनातनी योद्धा सड़कों पर उतर आए। रैली की शुरुआत सायंकाल 4 बजे पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल से हुई, जहाँ से हजारों की संख्या में सनातनी जयघोष करते हुए आगे बढ़े। सभी ने एक स्वर में कहा कि सनातनधर्मियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, देगे मुंहतोड जवाब।

रैली का मुख्य पड़ाव सुभाष चौराहे पर सामूहिक 'वंदे मातरम' का गान रहा, जहाँ 'जय माँ भवानी' के गगनभेदी उद्घोष ने वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। रत्नेश दुबे, डॉ. सूर्य कुमार दुबे एवं अन्य कलाकारों की स्वर लहरियों ने उपस्थित जनसमूह में राष्ट्रभक्ति का ज्वार भर दिया।

हनुमत संग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का सबसे गौरवशाली क्षण वह था जब मालेगांव प्रकरण में 'भगवा आतंकवाद' के षड्यंत्र का दंश झेलने वाले और सनातन के लिए अपना जीवन होम करने वाले सनातनी योद्धा सुधाकर पुरी महाराज का ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन किया गया। सिविल लाइंस व्यापार मंडल, राष्ट्रीय हिंदू संगठनों, प्रबुद्ध वर्ग, चिकित्सकों एवं अधिवक्ताओं ने सुधाकर पुरी जी का विशाल पुष्पहारों से भव्य स्वागत कर उनके त्याग और तपस्या को नमन किया। उनके साथ सनातन सेना के मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र दुबे और मनोज दुबे को भी सम्मानित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर पुरी महाराज ने वर्तमान परिस्थितियों पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह बेटियों के खिलाफ जेहाद और अत्याचार बढ़ रहा है, वह बर्दाश्त से बाहर है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अब सहने का समय बीत गया है, अब प्रतिकार का समय है। उन्होंने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर पड़ोसी देशों में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

हनुमत संग के पदाधिकारियों, पूर्व जस्टिस जेसी श्रीवास्तव, धर्मेंद्र द्विवेदी और राजीव मिश्र ने सामाजिक एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि

सनातन एक विशाल वृक्ष है और समस्त जातियां उसकी टहनियां हैं। मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए हनुमत संग की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी योग माता, श्रीमती पांडे और सतीश द्विवेदी के कुशल संचालन में आयोजित इस सभा में हनुमत संग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र पांडेय 'शीलू' ने उपस्थित जनसमूह को सामूहिक शपथ दिलाई कि यदि शिखा, प्रतिभा सिंह और उष्मा मिश्रा ने सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा और अपनी डेमोग्राफी को बचाने का संकल्प लिया। आयुष मिश्रा, केशव गाय, गंगा, गीता, संत या सनातन संस्कृति का अपमान हुआ, या बेटियों पर अत्याचार हुआ, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

हनुमत संग के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ. अभिनव त्रिपाठी ने ऐतिहासिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए 'घर-घर हनुमान चालीसा' अभियान के माध्यम से संगठित होने का आह्वान किया। रैली और सभा का नेतृत्व दुर्गेश दुबे, गुह्य निषाद राज डॉ. बीके. कश्यप, डॉ. सत्यानंद यादव, अभिषेक शुक्ला एवं विनोद मिश्र ने किया। युवा शक्ति का नेतृत्व करते हुए सचिन सिंह, सौरभ सिंह, कार्तिकेय और आदित्य पाठक ने वंदे मातरम के गान में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पूरे आयोजन को डिजिटल माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने के लिए यश पांडेय एवं उनकी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर सक्रिय रूप से जुड़ी रही।

हुंकार रैली में चन्द्र प्रकाश यादव, हेमंत बनर्जी, बालेश यादव, सत्येंद्र दुबे, विवेकानंद तिवारी, सुप्रभात जी, एसपी. श्रीवास्तव, एम.सी. भद्रा, अवधेश निषाद, मनोज निषाद, राकेश पासी, मोटू पासी, केशव पांडेय, दिनेश यादव, आरपी. यादव, देवेंद्र श्रीवास्तव, राजीव मिश्र, चौथराम यादव, अजीत पांडेय, संजय गुप्ता, शैलेन्द्र मिश्र, मनोज मिश्र, नारू दादा, प्रदीप दत्त, देवेश बनर्जी, अमित बनर्जी, संतोष हेला, राजीव कनौजिया, सोनू सोनकर, शंभुनाथ अंशुल, दीपू सोनकर एवं गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर दुकान जी आदि उपस्थित रहे।

चकबंदी विभाग ने लगाई चौपाल बाबूपुर साथर व कादीपुर साथर गांव में की जनसुनवाई

राजस्व व चकबंदी मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। तहसील हंडिया क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर साथर एवं कादीपुर साथर में चकबंदी आयुक्त के निर्देश पर जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों की राजस्व एवं चकबंदी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।बैठक की अध्यक्षता उप संचालक चकबंदी प्रयागराज विजय कुमार शर्मा ने की। इस दौरान चकबंदी अधिकारी हंडिया डॉ. पारस नाथ यादव एवं सहायक चकबंदी अधिकारी हंडिया यशवंत कुमार समेत राजस्व कर्मचारी, चकबंदी कर्ता, लेखपाल तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण व किसान उपस्थित रहे।जनसुनवाई में वरासत संबंधी प्रकरण, बैनामा एवं उसके अनुपालन, नामांतरण के लंबित मामले, भूमि विवाद, अवैध कब्जे की शिकायतें तथा क्षेत्रफल एवं अभिलेखीय त्रुटियों जैसे मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने अभिलेखों का परीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विरासत एवं नामांतरण के मामलों में अनावश्यक विलंब न करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए।उप संचालक चकबंदी ने कहा कि चकबंदी कार्य पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और शासन की मंशा के अनुरूप संपादित किए जाएं। जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।बैठक के अंत में अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सभी लंबित प्रकरणों का

लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई ईआरओ हीरालाल सैनी ने एक सुपरवाइजर व दो बीएलओ का मानदेय रोका, चार को अंतिम चेतावनी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। विधानसभा क्षेत्र 254 फाफामऊ में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर ईआरओ फाफामऊ एवं नगर मजिस्ट्रेट हीरालाल सैनी ने सख्त कार्रवाई की है। नोटिस की सुनवाई तथा फॉर्म 6, 7 और 8 की समीक्षा के दौरान कार्य में शिथिलता पाए जाने पर एक सुपरवाइजर एवं दो बीएलओ के वेतन/मानदेय पर रोक लगाई गई, जबकि चार बीएलओ को अंतिम चेतावनी जारी की गई।जानकारी के अनुसार बूथ संख्या 154 के बीएलओ सौरभ शेखर एवं बूथ संख्या 337 के बीएलओ अभिताभ मिश्र (शिक्षामित्र) के कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर उनके मानदेय के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

वहीं बूथ संख्या 34, 255, 271 और 341 की बीएलओ क्रमशः पदमा शुक्ला, शिवानी पटेल, रेखा सिंह व पूनम लता को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया हैइसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर बूथ संख्या 1 से 10 तक के बीएलओ सुपरवाइजर रामकुमार के वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है।ईआरओ हीरालाल सैनी ने स्पष्ट कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्मिकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं शत-प्रतिशत शुद्धता के साथ कार्य पूर्ण

पांडेश्वर धाम में ब्राह्मण संगठनों ने किया सम्मान समारोह, यूसीसी बिल पर जताई आपत्ति

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। थरवई क्षेत्र स्थित पांडेश्वर धाम में नवयुवक ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण परिषद एवं गरुड़ ब्राह्मण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह एवं बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रमुख एवं पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री तथा प्रधानमंत्री के हमशक्ल के रूप में चर्चित अभिनंदन पाठक को भगवान परशुराम की प्रतिमा स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवयुवक ब्राह्मण समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मण एवं सवर्ण समाज विभिन्न नीतियों के कारण दबाव महसूस कर रहा है। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट, आरक्षण व्यवस्था तथा प्रस्तावित यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) बिल को लेकर अपनी आपत्ति जताई। वक्ताओं ने कहा कि समाज अब जागरूक और संगठित हो चुका है तथा अपने अधिकारों की रक्षा

के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाता रहेगा।बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि वे अपने सामाजिक सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे।इस अवसर पर ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र, गरुड़ सेवा संस्थान के अध्यक्ष आशीष तिवारी, नवयुवक ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मिश्र, महामंत्री प्रमोद शुक्ल, सचिव भुनेश शुक्ल, डॉ. पुष्कर त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष संजय पांडे, प्रमोद त्रिपाठी आजाद प्रतापगढ़ अध्यक्ष बी.के. त्रिपाठी सहित राम शिरोमणि मिश्र, संतोष द्विवेदी, अनुराग मिश्र, गुड्डू मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, कृष्णमूर्ति मिश्र समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कंट्रोल रूम से प्रश्न पत्र के स्ट्रांग रूम पर रखी जा रही नजर

परीक्षा के दौरान तीन दर्जन जिलों के 40 परीक्षा केन्द्रों को दी गयी चेतावनी

यूपी बोर्ड मुख्यालय, डीआईओएस कार्यालय में शिफ्ट वार कंट्रोल रूम में लगे है अफसर, कर्मचारी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान जिलों में बनाए गये 8033 परीक्षा केन्द्रों पर बनाए गये स्ट्रांग रूम में रखे गये प्रश्न पत्रों पर यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और जिलों में डीआईओएस के यहां बनाए गये कंट्रोल रूम से स्ट्रांग रूम पर दिन, रात नजर रखी जा रही है। यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज ने तीन दर्जन जिले के 40 परीक्षा केन्द्रों पर बनाए गये स्ट्रांग रूम में भीड होने पर, दरवाजा खुला होने पर, लाइट जाने पर और अन्य मामलों को लेकर केन्द्र व्यवस्थापक को चेतावनी दी गयी है। यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले के एक परीक्षा केन्द्र के स्ट्रांग रूम में अधिक लोगों के घुसने पर बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज ने उस स्ट्रांग रूम की तुरंत फोटो भेजते हुए डीआईओएस को जानकारी दी, इस पर संबंधित जिले के डीआईओएस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई किया। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के सभी केन्द्रों पर बनाए गये स्ट्रांग रूम पर दिन और रात आनलाइन बोर्ड मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। बोर्ड मुख्यालय के अफसरों और कर्मचारियों की तीन शिफ्ट में डियूटी लगायी गयी है। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी प्रकार की गडबडी नही हो रही है।

उधर, यूपी बोर्ड मुख्यालय के सबसे

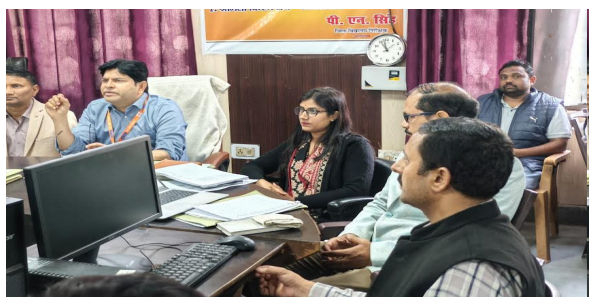

संवेदनशील प्रयागराज जिले के परीक्षा केन्द्रों पर बने स्ट्रांग रूम पर डीआईओएस कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से दिन, रात नजर रखी जा रही है। इस दौरान कंट्रोल रूम में दर्जनभर कर्मचारी अलग - अलग पालियों में डियूटी कर रहे है। उनके साथ प्रभारी भी लगे है जिससे कि जिलों के परीक्षा केन्द्रो पर बने स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा सके। इसकी समीक्षा डीआईओएस पीएन सिंह कर रहे है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रो के स्ट्रांग रूम पर 24 घण्टे नजर रखी जा रही है जिससे कि कोई गडबडी ना होने पाए। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सात दस्ते गठित किए गये है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी परीक्षा केन्द्र के स्ट्रांग रूम से कोई शिकायत नही मिली है।

अभी तक हुए कार्यों की हुई समीक्षा, जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान है सम्भव - नगर आयुक्त

नगर निगम के साप्ताहिक बैठक में सभी जोन के अधिकारीगण रहे उपस्थित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। नगर निगम में आज मंगलवार को सम्भव जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त, श्री सीलम साईं तेजा जी नगर निगम के अपने क्षेत्रों से आए जनमानस की समस्याओं को सुना। नगर आयुक्त ने कहा कि समस्याओ का त्वरित निस्तारण करना हमारा दायित्व है।

जनसुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने अश्वासन दिया कि जनसुनवाई में आई शिकायतो में पेयजल तथा सड़क-नाली निर्माण तथा अतिक्रमण आदि से जुड़ी रहती है । नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल तथा नालों और नालियों की साफ-सफाई तथा जाम नालियों की समस्या है उसे मरम्मत या निर्माण कार्य करने को कहा इस दौरान शहर में विभिन्न स्थानों चबूतरे, पेयजल, शौचालय/ यूरिनल, जल की समस्याओं, हाउस टैक्स तथा नगर की सड़कों पर सफाई की व्यवस्था किये जाने का ध्यान रखने को कहा इसी क्रम में साफ-सफाई मार्ग प्रकाश, मलवा, अतिक्रमण जैसी समस्या को तत्काल निस्तारण का आदेश को दिया।

सम्भव की बैठक में अपर नगर आयुक्त दीपेन्द्र यादव, अरविन्द

कुमार रॉय, राजीव कुमार शुक्ला दिनेश चंद्र सचान मुख्य अभियंता (सिविल), संजय कटियार मुख्य अभियंता (वि./या.), डाद महेश कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी, गौरव कुमार महाप्रबंधक जलकल पी. के. मिश्रा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, डाद विजय अमृत राज पशु चिकित्सा कल्याण विभाग , रामपूजन सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार जोनल अधिकारी जोन 1, संजय ममगई जोनल अधिकारी जोन 2, नवनीत शंखवार जोन 3, विकास जैन जोन 4, अखिलेश त्रिपाठी जोन 5, श्याम कुमार जोन 6, सौरभ यादव जोन 7, सुदर्शन चंद्र जोन 8 अनिल

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट पशु विकास दिवस के माध्यम से सर्वोत्तम सेवा में अग्रणी 1.55 लाख ग्रामीणों पर उत्पन्न किया सकारात्मक प्रभाव

वाराणसी। भारत की अग्रणी एनबीएफसी में से एक एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 14 फरवरी 2026 को अपनी प्रमुख पशु कल्याण एवं ग्रामीण आजीविका पहल, पशु विकास दिवस के आठवें संस्करण का सफल समापन किया। 'सर्वोत्तम सेवाः पशु, परिवार और प्रगति' की थीम पर आधारित इस पहल ने पशुओं के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण एवं स्थायी प्रगति को बढ़ावा देकर समग्र ग्रामीण विकास के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री नन्दी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन, आज भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक रूप में देखी जा रही है : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा, 2029-30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा रहा निर्णायक कदम

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029-30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ सिंगापुर एवं जापान की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात की। कई निवेशकों के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई एमओयू साइन हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर एवं जापान की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। मंत्री नन्दी ने सिंगापुर में एशिया पैसिफिक गूगल के अध्यक्ष संजय गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजिटल परिवर्तन, एआई के नेतृत्व में नवाचार और कौशल की पहल में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और भविष्य में तैयार कार्यबल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक समर्पित गूगल एआई और कौशल केंद्र की स्थापना की सम्भावनाओं पर चर्चा हुई।

इस दौरान सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गन किम योंग, उद्योग मंत्री के.के. से मुलाकात की। इस दौरान संस्थागत सहयोग को मजबूत करने, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और व्यापार, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और शासन ढांचे में उत्तर प्रदेश सिंगापुर सम्बंधों को गहरा करने पर चर्चा हुई।

सिंगापुर में सैट्स चांगी एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स हब का दौरा किया। उन्नत वायु कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला संचालन का दौरा किया।

जेवर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रकाश में यह यात्रा उत्तर प्रदेश के विमानन बुनियादी ढांचे और मल्टीमॉडल रसद पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अत्यधिक प्रासंगिक थी। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिंगापुर में टीम यूपी को लगभग ?1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ?60 हजार करोड़ के एमओयू 'इन्वेस्ट यूपी' द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह निवेश प्रदेश को 1 ट्रिलियन

डॉलर इकॉनमी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया आज पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है। निवेशकों को उत्तर प्रदेश में हो रही प्रत्येक गतिविधि की जानकारी है। यही कारण है कि कम समय में ही यूपी को इतना बड़ा निवेश प्राप्त हुआ है।

प्रदेश ने बीते साढ़े आठ-नौ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, सर्विस सेक्टर और जन-कल्याण के क्षेत्रों में तेज गति से विकास किया है। आज भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक रूप में देखी जा रही है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे में भी कुछ कंपनियों ने पहले से निवेश किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति निवेशकों की धारणा में 360 डिग्री का सकारात्मक परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने उन अत्याधुनिक स्थलों का भी दौरा किया, जहां सामान्य लोगों का प्रवेश कठिन होता है। विशेष रूप से शीघ्र शुरू होने वाले जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो सुविधा और एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग) विकसित करने के लिए सिंगापुर की दक्षता का अध्ययन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में भारत सहित विश्व के अनेक विमान अपने एमआरओ कार्यों के लिए सिंगापुर आते हैं। यह सुविधा भारत में, विशेषकर जेवर में विकसित की जा सकती है। निवेशकों ने इस विषय पर गंभीर तैयारी कर रखी है और वे उत्तर प्रदेश के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

भिवंडी में आधी रात आगजनी से दहशत

अज्ञात शरारती तत्वों ने 5 दुपहिया वाहनों को जलाया, पुलिस जांच में जुटी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर के नारपोली क्षेत्र स्थित भंडारी चौक के अनंता नगर इलाके में देर रात अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा पांच दुपहिया वाहनों को आग के हवाले किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आगजनी की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया।

मिली जानकारी के अनुसार घटना देर रात उस समय हुई जब रिहायशी परिसर के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने पार्किंग में खड़ी दुपहिया गाड़ियों को निशाना बनाते हुए उनमें आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक पांच बाइक जलने लगीं।आग की तेज लपटें और धुआं उठता देख स्थानीय निवासियों की नींद खुल गई। लोगों ने तुरंत बाहर निकलकर बाल्टियों और पाइप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पांचों दुपहिया वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे।घटना की सूचना मिलते ही भोईवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में आगजनी की आशंका जताई जा रही है। यह वारदात पुरानी रंजिश का परिणाम है या फिर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है।पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है तथा स्थानीय नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से अनंता नगर परिसर के रहवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।नागरिकों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

महापौर-उपमहापौर बनते ही चली तबादला एक्सप्रेस...

भिवंडी मनपा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मानिक जाधव को प्रभाग अधिकारी पद से हटाया गया

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका में नए महापौर और उपमहापौर के पदभार संभालते ही प्रशासनिक स्तर पर तबादलों की एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है। मनपा प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग और पदभार में बड़ा फेरबदल किया गया है। अचानक हुए इस बदलाव से पालिका प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार शैलेश दोंदे (सहायक आयुक्त) को प्रशासन विभाग, वाहन विभाग, सुरक्षा विभाग,ग्रंथालय विभाग,अभिलेख व सामग्री विभाग, विधि विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा क्रीड़ा विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। फैसल क. तातली (प्रभारी अधीक्षक व विभाग प्रमुख) को सहायक आयुक्त (आरोग्य व स्वच्छता) पद का अतिरिक्त प्रभार देते हुए अन्न, बांधकाम एवं अतिक्रमण निष्कासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। माणिक जाधव (सहायक आयुक्त) को प्रभाग समिति क्रमांक-2 के प्रभाग अधिकारी पद से हटाकर कार्यालयीन अधीक्षक तथा जनगणना विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। विनोद साहेबराव मनोरे (सहायक आयुक्त - प्रशासन) को सहायक आयुक्त के रूप में प्रभाग समिति क्रमांक-2 का नया प्रभार दिया गया है। मनपा प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं होगा तथा प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करना होगा। सूत्रों के अनुसार महापौर-उपमहापौर पद संभालने के तुरंत बाद हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को सत्ता परिवर्तन के बाद की प्रशासनिक पुनर्रचना माना जा रहा है। हालांकि मनपा प्रशासन ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है। एक साथ हुए इन तबादलों से यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भिवंडी मनपा में और भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

भिवंडी में पत्नी को बदनाम करने की साजिश!

पति ने सोशल मीडिया पर वायरल किया आपत्तिजनक वीडियो, आईटी एक्ट में केस

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए जाने का गंभीर मामला भिवंडी में सामने आया है। पति पर पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठी जानकारी फैलाकर उसकी छवि खराब करने का आरोप लगा है। भिवंडी शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार कापअली क्षेत्र की रहने वाली 43 वर्षीय शिक्षिका ने अपने पति श्रीनिवास पेंट्या वनम (45) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक महिला ने पूर्व में अपने पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पति ने बदला लेने की नीयत से पत्नी को बदनाम करने की साजिश रचा।आरोप है कि आरोपी ने एक न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिला के बारे में झूठे और आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए वीडियो प्रसारित किया। वीडियो में महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसके किसी युवक के साथ संबंध होने, पैसों के लेनदेन और अनुचित संबंधों जैसी बातें कही गईं। पीड़िता का आरोप है कि इस वीडियो के वायरल होने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा और मानसिक रूप से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को धमकी देते हुए गाली-गलौज भी की। भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। इस घटना ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और पारिवारिक विवादों के खतरनाक रूप को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

भिवंडी के गोदाम से लाखों का कपड़ा गायब..

मैनेजर ने ही कंपनी को लगाया चूना, 2.25 लाख का माल लेकर फरार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी के पिंपलास स्थित इंडस्ट्रियल परिसर में एक कंपनी के मैनेजर द्वारा ही लाखों रुपये का कपड़ा चोरी करने का मामला सामने आया है। कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर कोनगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मुंबई के लालबाग निवासी व्यापारी बाबूसिंह भवरसिंह राजपुरोहित (60) की सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस नामक कंपनी भिवंडी के पिंपलास स्थित भूमिवर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क में संचालित है। कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत इंद्रजीतकुमार बहेलिया (45), मूल निवासी उत्तर प्रदेश, पर भरोसे का फायदा उठाकर माल चोरी करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 15 नवंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 के बीच आरोपी ने कंपनी के गोदाम से अलग-अलग समय पर सफेद, काला, लाल, मरीन और नीले रंग का कुल 494.610 किलो कपड़ा गायब कर दिया। चोरी किए गए कपड़े की कुल कीमत लगभग 2 लाख 15 हजार 927 रुपये बताई गई है। आरोप है कि कंपनी के कामकाज और माल की जिम्मेदारी आरोपी के पास होने के कारण उसने पद का दुरुपयोग करते हुए कपड़ा बाहर निकालकर बेच दिया। स्टॉक की जांच के दौरान माल कम मिलने पर मामले का खुलासा हुआ। कोनगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 के तहत अमानत में खयानत और चोरी का मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

घर दिलाने के नाम पर 2.30 लाख की ठगी

निर्माणाधीन बिल्डिंग का झांसा देकर महिला से ऐंठी रकम, आरोपी फरार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।सस्ते में घर दिलाने का लालच देकर महिला से लाखों रुपये ठगने का मामला भिवंडी में सामने आया है। नारपोली पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठाणे निवासी संजना महेश कापडोसकर (44) ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक आरोपी सुरेश पाटिल और उमेश रोहेंकर ने आपस में साजिश रचकर भिवंडी के पूर्णा गांव स्थित दत्तनगरी रेसिडेंसी में निर्माणाधीन इमारत में फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने महिला को विश्वास में लेते हुए कहा कि कम कीमत में घर उपलब्ध कराया जाएगा। आरोपियों की बातों में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग समय पर कुल 1 लाख 30 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए। रकम लेने के बाद भी आरोपियों ने न तो फ्लैट दिया और न ही पैसे वापस किए। काफी समय तक टालमटोल करने के बाद जब महिला को ठगी का अहसास हुआ तो उसने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

डायरेक्ट केबल जोड़कर लाखों की बिजली चोरी, मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।शहर के गुलजार नगर इलाके में अवैध रूप से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान बिना मीटर सीधे बिजली लाइन जोड़कर भारी मात्रा में बिजली उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ है। शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हितेश अशोककुमार सुतार (39), व्यवस्थापक, ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक गुलजार नगर स्थित गयासुद्दीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाले मोहम्मद लतीफ मोहम्मद रईस सलमानी पर बिजली चोरी करने का आरोप है। बताया गया है कि 21 जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच आरोपी ने अपने आर्थिक लाभ के लिए बिजली कंपनी की अधिकृत लाइन से अवैध रूप से केबल जोड़कर सीधे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी थी। आरोपी ने बिना अधिकृत मीटर लगाए टोरेंट पावर कंपनी की लाइन से बिजली का उपयोग किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 3260 यूनिट बिजली का अवैध उपयोग किया, जिससे बिजली कंपनी को लगभग 65 हजार 178 रुपये का नुकसान हुआ। मामले का खुलासा निरीक्षण के दौरान हुआ, जिसके बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के संकेत दिए हैं।

'पर्यावरण संतुलन के लिए अहम': मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला का किया उद्घाटन, औषधीय पौधों को लेकर दिया संदेश

बुलढाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को औषधीय पौधों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारती है बल्कि मिट्टी की सेहत और पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य को जीवन की असली खुशी माना जाता है और स्वस्थ नागरिक देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि मुर्मू ने यह बात महाराष्ट्र के बुलढाणा के शेगांव में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करते हुए कही।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीमारी से बचाव व्यक्तिगत लाभ के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव भी कम करता है। मुर्मू ने कहा कि उनके जीवन का अनुभव और प्रकृति के करीब रहने का तरीका उन्हें आयुर्वेद और योग अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

जंगलों के खत्म होने पर जताई चिंता

इस दौरान राष्ट्रपति ने चिंता जताई कि जंगलों के खत्म होने और औषधीय पौधों की कमी के कारण आज अनुसंधानकर्ता भी दवाइयों के लिए आवश्यक पौधों को जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुर्मू ने कहा कि औषधीय पौधों की खेती को सरकार पर निर्भर न रहकर बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में 'आरोग्यम् परमं सुखम्' कहा गया है, यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी खुशी है।

उन्होंने कहा कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा (नैचुरोपैथी), सिद्ध और यूनानी विधियां लोगों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष विभाग ने पिछले दशक में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। नए एआईआईएमएस अस्पतालों में आयुष विभाग स्थापित किए गए हैं और सोवा रिग्पा संस्थान लेह में शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शेगांव के गजानन मंदिर में पूजा-अर्चना भी की

उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान, नवाचार और वैश्विक सहयोग से आयुष को सरल, सुलभ और लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। इसके जरिए इसे समकालीन स्वास्थ्य प्रणाली में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति ने शेगांव स्थित गजानन महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने गजानन महाराज के जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित बताया और उनके 'गण गण गणत बोते' के संदेश को सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण का मार्गदर्शन बताया।

PM-CM की बर्खास्तगी वाले विधेयकः संसदीय समिति जानेगी विपक्ष शासित राज्यों की राय, कर्नाटक-तेलंगाना को न्योता

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की अनुमति देने वाले विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति कर्नाटक और तेलंगाना जैसे विपक्षी शासित राज्यों के विचार आमंत्रित करेगी। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य के विचार सुने, जिसने 'संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025' का पूर्ण रूप से समर्थन किया।

मध्य प्रदेश का राज्य के मुख्य सचिव ने प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने समिति के सामने कहा कि राज्य विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह सहमत है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भी संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने समिति को कुछ सुझाव दिए।

दो कानूनी अनुसंधान संगठनों ने विधेयक पर जताई असहमति

सूत्रों के अनुसार, पैनल ने दो कानूनी अनुसंधान संगठनों के विचार सुने, जिन्होंने प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से पूरी तरह असहमति व्यक्त की और संशोधन सुझाए। हालांकि, उन्होंने पैनल को बताया कि विधेयक लाने में भारत सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं

है। सूत्रों ने बताया कि पैनल के सदस्य विपक्षी शासित राज्यों के विचार जानने के लिए सर्वसम्मति से सहमत हुए और कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों को बुलाने पर भी सहमत हुए।

पैनल ने यह भी कहा कि वह जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है, उन्हें भी इस मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। इन राज्यों में केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं।राज्यों को बाद में आमंत्रित किया जाएगा क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष शासित राज्यों से भी ली जाएगी राय

बुधवार की बैठक लगभग तीन घंटे तक चली, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक घंटा दिया गया। संसदीय समिति की अध्यक्ष सारंगी ने कहा कि यह पैनल की छठवीं बैठक है और अगली बैठक 10 मार्च को बुलाई जाएगी। अब तक समिति की छह बैठकों में 14 संगठनों और दो राज्यों ने समिति के समक्ष अपनी बात रखी है। इससे पहले, राजस्थान राज्य ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पैनल के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तावित कानून के प्रमुख प्रावधानों का समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

इस संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। अगर उन्हें गंभीर आपराधिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है। जिनके लिए पांच साल या उससे अधिक की कारावास की सजा का प्रावधान है।

'मौसा ही मेरे शौहर हैं, मैं उनकी दूसरी बीवी बनूंगी' प्यार में पागल हुई सगी भांजी

बीच सड़क घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा; मौसी के उड़े होश

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है। जहां एक युवती अपने ही सगे मौसा (खालू) के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हुई कि उसने दुनियादारी और लोक-लाज की सारी दीवारें तोड़ दीं। युवती बीच सड़क पर चिल्ला-चिल्लाकर जिद करती रही कि वह अपने मौसा की दूसरी पत्नी बनकर रहना चाहती है। मामला फतेहपुर के शादीपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि युवती अपने मौसा के घर रहने आई थी। जब उसके घरवाले उसे वापस ले जाने पहुंचे, तो युवती ने जाने से साफ इनकार कर दिया। वह सड़क पर ही चीखने-चिल्लाने लगी कि मुझे मौसा के साथ ही रहना है। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और करीब कई घंटों तक यह हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हैरानी की बात यह है कि मौसा पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। जब लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने बेबाकी से कहा कि सबकी दो-दो बीवियां होती हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है और मैं उनकी पत्नी बनकर रहूंगी। आखिरकार, परिजनों ने उसे जबरन पकड़कर ऑटो में बैठाया और रोती-चिल्लाती युवती को घर ले गए। इस पूरे विवाद की जड़ 18 महीने पुरानी है। युवती की मौसी ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था और उनका ऑपरेशन हुआ था, तब उन्होंने अपनी सगी बहन की बेटी (भांजी) को मदद के लिए घर बुलाया था।

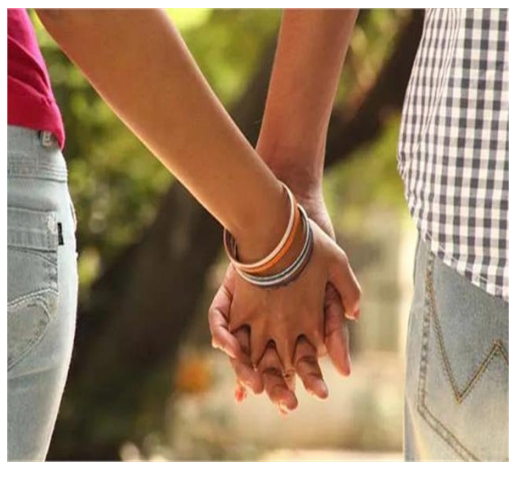

साक्षी महाराज के बयान पर यति नरसिंहानंद का पलटवार

कहा- सवर्णों को '90 प्रतिशत' के नाम पर डराने

गाजियाबाद **(एजेंसी)**। जनवरी 2026 में जारी यूजीसी के नए 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' नियमों पर जाति-आधारित भेदभाव के दायरे में ओबीसी को शामिल करने और सामान्य वर्ग के प्रति कथित भेदभाव के कारण बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसी बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक बयान सामने आया जिसे लेकर यति नरसिंहानंद गिरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। यति नरसिंहानंद गिरी, जो गाजियाबाद स्थित शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, ने एक वीडियो जारी कर भाजपा सांसद साक्षी महाराज को जवाब दिया है। वीडियो संदेश में यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि साक्षी महाराज को जो भी राजनीतिक पहचान और पद मिला है, वह राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण मिला

है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज साक्षी महाराज तथाकथित सवर्णों को '90 प्रतिशत' के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार सवर्ण समाज के समर्थन के बिना वे कभी चुनाव नहीं जीत सकते थे।महामंडलेश्वर ने कहा कि जिन लोगों ने साक्षी महाराज को हमेशा सम्मान दिया, आज उन्हीं को वे अन्य वर्गों के साथ मिलकर दबाव में लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे 'शर्मनाक' करार दिया।

यति नरसिंहानंद गिरी ने यह भी याद दिलाया कि साक्षी महाराज पहले पिछड़ों की उपेक्षा का मुद्दा उठाकर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन वहां सफलता न मिलने के बाद फिर भाजपा में लौट आए। उन्होंने इसे अवसरवादिता बताते हुए कहा कि आत्ममंथन करने के बजाय दूसरों को धमकाना उचित नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, साक्षी महाराज की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

टी20 विश्व कप : अहमदाबाद स्टेडियम की पिच पर केशव महाराज का बड़ा बयान, बोले- हर मैच में बदल जाता है चुनौती

अहमदाबाद (**एजेंसी**)। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने साफ कहा है कि एक ही वेन्यू पर ज्यादा मैच खेलना उनकी टीम के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं है। उनका मानना है कि असली कुंजी हालात के मुताबिक खुद को जल्दी ढालने में है। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक बार अहमदाबाद से बाहर गई है, जब उसने नई दिल्ली में यूएई का सामना किया था। 1 मार्च को उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाहर खेलना है।

महाराज ने मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सफर नहीं करना अच्छा लगता है, लेकिन पिच के लिहाज से हर मैच अलग रहा है। हमने यहां चार मुकाबले खेले और हर बार परिस्थितियां बदलीं। मैं इसे बड़ा एडवांटेज नहीं मानता। असली बात है कि आप विपक्ष से जल्दी हालात के मुताबिक ढलें और अपने प्लान को सही तरीके से लागू करें।'दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मुकाबले में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को हराकर आत्मविश्वास हासिल किया है। हालांकि महाराज ने कहा कि टीम ज्यादा उत्साहित होकर बहक नहीं रही।

'भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद कैंप में ऊर्जा थी, लेकिन अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना है और लगातार बेहतर करना है।' सुपर-8 में दोनों टीमें अब तक अजेय हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका यह मुकाबला जीत लेती है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। फिर भी महाराज ने कहा कि टीम एक-एक मैच पर फोकस कर रही है।'भारत के खिलाफ मैच हमारे लिए बड़ा था। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। हमें फिर से नई रणनीति के साथ उतरना होगा। वे विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।' यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका का टूर्नामेंट में पहला दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला मैच होगा। महाराज ने माना कि इस समय की परिस्थितियों में ढलना जरूरी होगा। 'शुरुआत में मैदबाज फीडबैक देते हैं। विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक परिस्थितियों को पढ़ने में माहिर हैं। हमें स्लोअर बॉल, कटर या लेंथ में बदलाव जैसे विकल्पों पर लगातार संवाद बनाए रखना होगा।' महाराज ने कहा कि सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ी टीम के लिए छोटे-छोटे पहलू निर्णायक होंगे। 'मैच के दिन उन एक प्रतिशत मौकों को पकड़ना जरूरी है। अगर हमारी योजना स्पष्ट रही और हम उसे सही तरीके से लागू कर पाए, तो वही हमारे नियंत्रण में है।'

लगातार असफल हो रहे जोस बटलर के बचाव में उतरे कप्तान हैरी ब्रूक, आलोचकों को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। मंगलवार को पालेकेले में पाकिस्तान के करीबी मुकाबले में दो विकेट से जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर इस टूर्नामेंट में बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं और अब तक सिर्फ 62 रन ही बना पाए हैं। हालांकि, पाकिस्तान पर जीत के बाद उनके कप्तान हैरी ब्रूक ने उनका समर्थन किया है।

जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्रूक से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने पूर्व कप्तान के बल्ले से फॉर्म को लेकर चिंता है, तो 27 वर्षीय ब्रूक ने कहा कि नहीं, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, वह विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। उन्होंने हर स्तर पर कमाल किया है। उन्होंने वनडे और टी20 में विश्व कप जीते हैं और यह सिर्फ समय की बात है। इंग्लैंड के ग्रुप स्टेज मैचों में बटलर ने नेपाल के खिलाफ 26 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 21 रन, स्कॉटलैंड के खिलाफ तीन रन और इटली के खिलाफ तीन रन बनाए। सुपर एट के पहले मैच में बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ सात रन बनाए और मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ दो रन बनाए।

बटलर की फॉर्म को लेकर मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रूक ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि लोगों को उन्हें थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि विश्व क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 500 से अधिक टी20 मैच खेले हैं, इंग्लैंड के लिए 150 से अधिक मैच खेले हैं, और उनका औसत अभी भी 35 है और स्ट्राइक रेट 145 है। तो हां, वह यकीनन हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। लेकिन हां, मुझे लगता है कि लोगों को शायद उन्हें थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए।

35 वर्षीय बटलर ने इंग्लैंड के लिए 153 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 34 के औसत और 147 के स्ट्राइक रेट से 4012 रन बनाए हैं। हाल ही में, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी बन गए हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साहिबजादा फरहान (45 गेंदों में 63 रन, सात चौके और दो छक्के सहित) ने टूर्नामेंट में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखा और बाबर, फखर जमान (16 गेंदों में 25 रन, दो चौके और दो छक्के सहित) और शादाब खान (11 गेंदों में 23 रन, चार चौके सहित) की पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने 164/9 का स्कोर बनाया।

टीसीएस को एआई से डर नहीं, राजस्व में 'कमी' के लिए तैयार : सीईओ कृतिवासन

मुंबई (**एजेंसी**)। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कृत्रिम मेधा (एआई) से 'डरी हुई' नहीं है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने सहयोगियों द्वारा विकसित एआई टूल्स के कारण राजस्व में होने वाली 'कमी' के लिए भी तैयार है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के. कृतिवासन ने यहां वार्षिक एनटीएलएफ कार्यक्रम में कहा कि कंपनी यह देख रही है कि 'कुशल' युवा कर्मचारियों की तुलना में वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी एआई-आधारित समाधान तैयार करने में धीमे हैं।

कृतिवासन ने कहा, ''हम अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे (ग्राहकों के पास) जाएं और एआई का उपयोग करें, भले ही इससे हमारे राजस्व में कमी आए।'' उन्होंने कहा कि टीसीएस इस बात पर जोर दे रही है कि उसके छह लाख से अधिक कर्मचारियों में प्रत्येक एआई में पारंगत हो। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी इस नई प्रौद्योगिकी के चलते नौकरियों में छंटनी को लेकर 'डरी' हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के तहत टीसीएस ने अपने सहयोगियों से यह पता लगाने के लिए कहा है कि वे परियोजनाओं में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, भले ही इसके कारण राजस्व में कुछ नुकसान उठाना पड़े। कृतिवासन ने कहा कि हर कोई एआई कौशल सीखना चाहता है और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने साथ ही जोड़ा कि जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी बनते हैं, वे बहुत कुछ पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर कुछ निर्माण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को मेहनत करनी होगी और एआई टूल का उपयोग करके समाधान बनाने होंगे। उन्होंने एआई को एक सभ्यतागत बदलाव करार दिया और कहा कि इससे ज्ञान सर्वसुलभ होगा।

पाकिस्तान की सिदरा अमीन को आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन पर लगी फटकार

दुबई (**एजेंसी**)। पाकिस्तान महिला टीम की खिलाड़ी सिदरा अमीन को आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई गई है। सिदरा को आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के आर्टिकल 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जोअंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या वस्त्र, मैदान उपकरण या फिटिंग का दुरुपयोग'से संबंधित है। इसके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई।

इसके अलावा, सिदरा के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। यह उनके लिए यह 24 महीने में दूसरी गलती थी, जिससे उनके डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या दो हो गई। यह घटना रविवार को ब्लोमफोंटेन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की पारी के 24वें ओवर में हुई, जब आउट होने के बाद, सिदरा ने क्रीज छोड़ने से पहले अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया। पांच अक्टूबर को भारत के खिलाफ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप 2025 मैच के दौरान इसी गलती के लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया था। सिदरा ने अपनी गलती मान ली और अंतरराष्ट्रीय पैनल ऑफ मैच रेफरी के शैंड्रे फ्रिट्ज़ द्वारा सुझाई गई सजा को स्वीकार कर लिया, इसलिए इस पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर केरिन क्लास्टे और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर लॉरेन एजेनबैग और चौथे अंपायर स्टेसी लैके ने सिदरा पर आरोप लगाये थे।

ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी को निदेशक मंडल में किया शामिल

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। यात्रा एवं आतिथ्य मंच ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने बाजार नियामक सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी को अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त करने की बुधवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा कि यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब प्रिज्म सार्वजनिक बाजारों में पहुंचने और विस्तार की दिशा में अपने निदेशक मंडल एवं कॉरपोरेट कामकाज ढांचे को और मजबूत करना चाहती है। प्रिज्म के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कहा, ''अजय को पूंजी बाजार विनियमन और सार्वजनिक संस्थागत नेतृत्व में गहन अनुभव है। प्रिज्म जब विस्तार और उच्च कामकाज मानकों के साथ दीर्घकालिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब उनका अनुभव अत्यंत मूल्यवान होगा।'' अजय त्यागी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1984 बैच के अधिकारी हैं। वे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन रह चुके हैं। 2017 से 2022 तक सेबी प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत के पूंजी बाजार की निगरानी, विनियामक एवं प्रवर्तन ढांचे को सुदृढ़ करने, निवेशक संरक्षण एवं प्राथमिक व द्वितीयक बाजार गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी निभाई। वर्तमान में वे कई भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। त्यागी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक तथा कंप्यूटर साइंस में परास्नातक हैं। उनके पास हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में मास्टर डिग्री भी है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि प्रिज्म ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास गोपनीय मार्ग के जरिये 6, 650 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। प्रस्तावित आईपीओ से कंपनी का मूल्यांकन सात से आठ अरब अमेरिकी डॉलर के दायरे में होने की उम्मीद है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

सहायक आयुक्त एफ/दक्षिण विभाग
क्रमांक: AE/SWM/61506/F/South दिनांक : 24.02.2026

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त द्वारा निम्नलिखित ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है:

कार्य का नाम	बयाना राशि जमा	निविदा शुल्क	बोली प्रारंभ दिनांक एवं समय	बोली समाप्ति दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5
एसडब्ल्यूएम विभाग एफ/दक्षिण वार्ड में उप प्रमुख पर्यवेक्षक कार्यालय में उपलब्ध मौजूदा उपयोगी स्थान का नवीनीकरण/पुनर्सज्जा (**क्रमांक : 2026_MCGM 1281351 _1**)	रू. 27,500/-	रू.7260/- + 18% जीएसटी	25.02.2026 11:00 Hrs.	02.03.2026 11:00 Hrs.

निविदा की प्रति बीएमसी के पोर्टल (http://www.mcgm.gov.in) के 'ई-प्रोक्योरमेंट' अनुभाग से डाउनलोड की जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए http://www.mcgm.gov.in पर लॉग ऑन करें।

हस्ताक्षर/-
(श्री संजय मोहिते)
सहायक अभियंता
एसडब्ल्यूएम एफ/दक्षिण वार्ड

पीआरओ/3104/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

मृणाल ठाकुर की फिल्म देख लोग हो रहें दीवाने, 5वें दिन लम्बा हुआ कारोबार

मुंबई। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने सहर में' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म ने अपने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को मंडे टेस्ट के बाद अपनी पकड़ को काफी हद तक संभलकर रखा है। युवाओं के बीच फिल्म की लोकप्रियता और इसके गाने ने इसे वर्किंग डेज में भी चर्चा में बनाए रखा है। आइए जानते हैं कि मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इसकी स्थिति क्या है।

रिलीज के पांचवां दिन किसी भी फिल्म के लिए चैलेंज से भरा होता है। 'दो दीवाने सहर में' के शुरुआती रिपोर्ट इस तरह हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने 5वें दिन लगभग 39 लाख का कारोबार किया है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार के कलेक्शन में मामूली गिरावट देखी गई है। यह स्थिरता दिखाती है कि मृणाल और सिद्धांत की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है। 5 दिनों के बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब लगभग 5।19 करोड़ के आंकड़े को छू रहा है।

फिल्म की शुरुआत औसत रही थी, लेकिन वीकेंड के बाद भी फिल्म का पूरी तरह से न गिरना मेकर्स के लिए राहत की बात है। पहले दिन फिल्म ने 5।19 करोड़ की कमाई की।

बॉक्स ऑफिस पर 'ओ रोमियो' जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद यह फिल्म टिकी हुई है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की पहली बार पर्दे पर साथ देखना दर्शकों के लिए एक नया अनुभव है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को न्यूरल और क्यूट बताया जा रहा है। फिल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं यह फिल्म मेट्रो शहरों और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिल्म का बजट लगभग 12-15 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए,

1।25 करोड़ की कमाई की वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 1।50 करोड़ कमाए। फिल्म ने पहले रविवार को 1।45 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले सोमवार को फिल्म ने 60 लाख की कमाई की और पांचवें दिन फिल्म ने 39 लाख की कमाई की। इस तरह से फिल्म ने 5 दिनों में फिल्म को अपना बजट वसूलने के लिए कम से कम दूसरे वीकेंड तक थिएटर्स में टिकना होगा। शुक्रवार को नई रिलीज के आने से पहले फिल्म को कम से कम 6-7 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा ताकि यह एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके।

पश्चिम रेलवे

मानसून-पूर्व रखरखाव कार्यों का आउटसोर्सिंग

वरिष्ठ डीईई/टीआरएस/बीएल इलेक्ट्रिक लोको शेड, वलसाड ई-टेंडर संख्याः EL/TRS/BL/25-26/WO/04R दिनांक 17/02/2026 को आमंत्रित करता है। कार्यः ईएलएस/वलसाड स्थित सभी लोकोमोटिव के मानसून-पूर्व रखरखाव कार्यों का दो वर्ष की अवधि के लिए आउटसोर्सिंग। कार्य की अनुमानित लागतः 49,25,400 रुपये। ईएमडीः 98,500 रुपये। जमा करने की तिथि और समयः 14.03.2026, दोपहर 12:00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि और समयः 14.03.2026 को दोपहर 12:30 बजे। वेबसाइट विवरणः www.ireps.gov.in 1155

Like us on: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

रखरखाव कार्य

सीनियर डीएमई (कंपनी)/बीसीटी निविदा सूचना संख्याः एम137-डीपीआर-वीबीई-2025, दिनांक 20-02-2026 आमंत्रित करता है। कार्य का नामः वंदे भारत ट्रेनों के लिए रखरखाव अवसंरचना और रखरखाव सुविधाओं के विकास/उन्नयन के प्रस्तावित कार्य के संबंध में डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्श सेवा। कार्य की अनुमानित लागतः 10,00,000 रुपये (सभी कर सहित)। बोली सुरक्षा राशिः 20,000 रुपये। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समयः 23.03.2026 को दोपहर 3:00 बजे अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

Like us on: facebook.com/WesternRly

स्मार्टफोन 30 अरब डॉलर के साथ देश का अग्रणी निर्यात खंड बनाः वैष्णव

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2025 में देश में बने 30 अरब डॉलर मूल्य के स्मार्टफोन निर्यात किए गए और अब स्मार्टफोन भारत का शीर्ष निर्यात खंड बन चुका है। वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत अब 'दुनिया का स्मार्टफोन विनिर्माण केंद्र' बनता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-दिसंबर, 2025 के दौरान देश का स्मार्टफोन निर्यात 30 अरब डॉलर रहा। देश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए (करीब 60 अरब डॉलर) के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ, जबकि इस दौरान निर्यात करीब दो लाख करोड़ रुपये (लगभग 22 अरब डॉलर) का रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का कुल निर्यात वर्ष 2025 में चार लाख करोड़ रुपए (करीब 44 अरब डॉलर) के पार पहुंच गया है। इस वर्ष चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है। बाजार शोध संस्था काउंटरपॉइंट रिसर्च के सह-संस्थापक और शोध उपाध्यक्ष नील शाह ने कहा कि एप्पल ने चीन पर अमेरिकी शुल्क लगने के बाद भारत में विनिर्माण बढ़ाकर देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। शाह ने कहा, ''भारत में 2025 में लगभग 30 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन होने का अनुमान है और हर चार में से एक स्मार्टफोन को निर्यात किया गया।'' उच्च औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) वाले अमेरिकी बाजार में एप्पल, सैमसंग और मोटोरोला की मजबूत मांग ने निर्यात मूल्य को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

शुद्धिपत्र

विषय: पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में गोधरा के निकट टिम्बा रोड स्टेशन पर वैगनों में सीधे लोड की जाने वाली 50 मिमी आकार की मशीन से क्रश की गई 4,23,395 घन मीटर स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति संबंधी कार्य हेतु **निविदा संख्या DRM BRC 185 of 2025-26** में शुद्धिपत्र।उपरोक्त निविदा के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि निविदा दस्तावेज़ के तकनीकी अनुपालन (Technical Compliance) के अंतर्गत निम्नलिखित धारा जोड़ी जाती है:धारा संख्या 7 – तकनीकी अनुपालन (अनिवार्य): यह निविदा ₹20 करोड़ से अधिक विज्ञापित मूल्य की है, जिसमें पात्रता मानदंडों में बोली क्षमता (Bid Capacity) भी शामिल है। अतः निविदाकार तभी पात्र माना जाएगा जब उसकी उपलब्ध बोली क्षमता, जीसीसी अप्रैल-2022 के परिशिष्ट-VI, भाग-I संशोधन पर्ची संख्या 1 (प्रति संलग्न) के अनुसार, वर्तमान निविदा के कुल बोली मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो। यह शर्त अनुमन्य (अनिवार्य) मानी जाएगी तथा तकनीकी अनुपालन मानदंड का अभिन्न हिस्सा होगी। निविदा की अन्य सभी शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

BRC 372

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) अहमदाबाद ⇌ मंगलुरु और इंदौर ⇌ खड़की के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाएगी
(वसई रोड होते हुए)

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियां	प्रस्थान	आगमन
09424	अहमदाबाद - मंगलुरु	27.02.2026 से 20.03.2026	16:00 बजे (शुक्रवार)	20:00 बजे (अगले दिन)
09423	मंगलुरु - अहमदाबाद	28.02.2026 से 21.03.2026	22:30 बजे (शनिवार)	02:15 बजे (सोमवार)

हॉल्ट: नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, माणगांव, खेड़, चिपलून, सावरदा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, थिविम, करमाली, मडगांव, कैनाकोना, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमता, मुर्देश्वर, भटकल, मूकाम्बिका दोनों दिशाओं में रोड बिंदूर, कुंडापुरा, उडुपी, मुल्की और सुरथकल स्टेशन।

संरचना: एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियां	प्रस्थान	आगमन
09324	इंदौर - खड़की	04.03.2026 से 25.03.2026	11:15 बजे (बुधवार)	02:50 बजे (अगले दिन)
09323	खड़की - इंदौर	05.03.2026 से 26.03.2026	04:40 बजे (गुरुवार)	23:55 बजे (उसी दिन)

हाल्ट: देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावला स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच।

समय, ठहराव और ट्रेन की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 09424 के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और ट्रेन नंबर 09324 के लिए बुकिंग 27.02.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और वेबसाइट पर शुरू होगी। ये ट्रेनें विशेष ट्रेनों के रूप में विशेष किराए पर चलेंगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

सभी आरक्षित टिकटों के लिए कृपया मूल पहचान पत्र साथ रखें।

गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन कर छात्रों को सौंपी डिजिटल ताकत

पणजी। गोवा के बेनाउलिम स्थित अवर लेडी ऑफ पट्रोसिनियो कम्युनिटी सेंटर में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पहल विधायक कैप्टन वेंजी वीगास द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गोवा के हर छात्र तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है।

इस ई-लाइब्रेरी में 10,000 से अधिक ई-बुक्स उपलब्ध हैं। सभी कक्षाओं के लिए वीडियो, सिमुलेशन और प्रैक्टिस मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। जेईई, नीट, क्लैट और 40 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट की सुविधा भी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी वही संसाधन मिल

सकें जो बड़े निजी स्कूलों के छात्रों को मिलते हैं।

गोवा की मौजूदा शिक्षा स्थिति कई सवाल खड़े करती है। राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 906 से घटकर 789 रह गई है। कुल लगभग 1,487 स्कूलों में से 238 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन जमीनी स्तर पर संसाधनों और शिक्षकों की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे समय में ई-लाइब्रेरी जैसी पहल छात्रों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है।

आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति का मॉडल पहले दिल्ली में लागू हुआ और फिर पंजाब में मजबूती से आगे बढ़ा। पंजाब में आज लगभग 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। राज्य सरकार ने 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजा, 216 प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय में और 199 हेडमास्टरों को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षित किया गया। सरकारी स्कूलों के लिए 1,908 कैंपस मैनेजर और 1,316 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए, जिससे स्कूलों का माहौल सुरक्षित और व्यवस्थित बना।

आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य साफ है, सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाना। पार्टी का मानना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे आगे चलकर रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि भविष्य बदलने का साधन है।

'बदलते स्वरूप में सशस्त्र सेनाओं को तकनीक आधारित युद्ध की ओर बढ़ना चाहिए', जनरल अनिल चौहान का बयान

हैदराबाद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज का युद्ध सिर्फ जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई इंटरनेट, तकनीक और लोगों के दिमाग (सोच) तक भी पहुंच गई है। इसलिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सिर्फ नेटवर्क के जरिये काम करने (नेट-सेंट्रिक ऑपरेशन) से आगे बढ़कर स्मार्ट और तकनीक आधारित युद्ध (इंटेलिजेंट वॉरफेयर) की ओर बढ़ना होगा।

जनरल चौहान ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन कॉलेज (सीडीएम) में आयोजित वार्षिक सेमिनार को संबोधित किया। सीडीएस ने कहा, आज का युद्ध तेजी से बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ मैदान में आमने-सामने नहीं होती, बल्कि तकनीक, साइबर और जानकारी के जरिये भी लड़ी जाती है। यानी युद्ध में पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ नई तकनीक और बिना सीधे टकराव के तरीके भी शामिल हो गए हैं। भारत को ऐसी मजबूत रणनीतिक क्षमता विकसित करनी चाहिए, जो परमाणु हथियारों के बिना भी दुश्मन को रोक सके। इससे किसी भी तनाव या टकराव की स्थिति में देश हर स्तर पर मजबूती से जवाब दे सके और जीत हासिल कर सके।

उन्होंने कहा, सेना को सिर्फ अलग-अलग क्षेत्रों (जमीन, हवा, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष) में काम करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर क्षेत्र में एक साथ और पूरी ताकत से काम करने की रणनीति अपनानी होगी, जिसे ऑल रियल्म ऑल डोमेन ऑपरेशन कहा जाता है।

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का दावा- दो साल में खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, जमीन पर दिखेगा बदलाव

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए तात्कालिक और लंबे समय की कई स्तरीय रणनीति के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत दिल्ली की सभी सड़कों पर लगातार स्प्रिंकलर से छिड़काव और सड़कों की स्थिति सुधार कर प्रदूषण को कम करने का काम हो रहा है तो दिल्ली से बाहर गुजरने वाली सड़कों को बेहतर बनाकर वाहनों का आवागमन आसान बनाया जा रहा है। इससे राजधानी के प्रदूषण में कमी आएगी।

'2027 के अंत तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हो जाएंगे गायब'

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र के स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में चार हजार के करीब ई बसें-उतारकर बसों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल दो वर्ष में 2027 के अंत तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ (गाजीपुर और भलस्वा सहित) पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि इस समय दिल्ली के इन कूड़े के पहाड़ों को 40 फीसदी से अधिक कम किया जा चुका है। दो साल के अंदर इसे जमीन की सतह तक ला दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि आश्रम-बदरपुर कॉरिडोर, कालिंदी कुंज सिग्नल-फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर, डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना कनेक्टिविटी कॉरिडोर, पंजाबी बाग-टिकरी बॉर्डर कॉरिडोर और महरौली-गुरुग्राम कॉरिडोर बनाकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। इससे आवागमन सही होगा और वाहनों के जाम होने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनाकर रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के लोगों को एक प्राणवायु देने का काम किया है। पूर्वी दिल्ली में 29 नए जन औषधि केंद्र और 11 अटल कैंटीन पूर्वी दिल्ली लोकसभा में खोले जा चुके हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार सभी कार्यों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य की शिकायत होने पर दिल्ली के लोग सरकार को इसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन इंजन की नहीं चार इंजन की सरकार है। वह चौथी इंजन है पार्टी का संगठन जो जनता के हितों के लिए लगातार काम करता है।

'एमिली इन पेरिस' से 'ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़' तक, लिली कोलिन्स निभाएंगी महान अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न का किरदार

मुंबई। नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज़ 'एमिली इन पेरिस' की स्टार लिली कोलिन्स अब पुराने हॉलीवुड के सुनहरे दौर को पर्दे पर जीवंत करने के लिए तैयार हैं। लिली को अगली फिल्म में स्क्रीन लीजेंड ऑड्रे हेपबर्न की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। यह फिल्म 1961 की कालजयी रोमांटिक कॉमेडी 'ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़' के निर्माण और उसके पीछे की अनकही कहानियों पर आधारित होगी।

अभी तक बिना टाइटल वाला यह प्रोजेक्ट कल्चरल क्लासिक बनाने पर फ़ोकस करेगा और सैम वासन की नॉन-फ़िक्शन किताब फ़िफ़्थ एवेन्यू, 5ँश ऑड्रे हेपबर्न, ब्रेकफ़ास्ट एट टिफ़नीज़ एंड द डॉन ऑफ़ द मॉडर्न वुमन से इंस्पायर्ड है। स्क्रीनप्ले एलेना स्मिथ ने लिखा है, जबकि डायरेक्टर का अनाउंसमेंट अभी बाकी है।

इस खबर को कन्फ़र्म करते हुए, लिली कॉलिन्स ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस रोल को एक लंबे समय से देखा गया सपना बताया। उन्होंने लिखा, 'लगभग 10 साल के डेवलपमेंट और ऑड्रे के लिए ज़िंदगी भर की तारीफ़ और प्यार के बाद मैं आखिरकार यह शेयर कर पा रही हूँ।' 'मैं जितना महसूस कर रही हूँ, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती।'

यह फ़िल्म उस दिलचस्प, अक्सर उतार-चढ़ाव वाले रास्ते को फिर से दिखाएगी, जिसकी वजह से ब्रेकफ़ास्ट एट टिफ़नीज़ सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गया। असल में 1958 में ट्रूमैन कैपोट ने एक नॉवेला के तौर पर पब्लिश की थी, यह कहानी 1940 के दशक के न्यूयॉर्क में एक राइटर पड़ोसी की नज़र से अजीब सोशलाइट हॉली गोलाईटली को दिखाती है। जब इसे स्क्रीन पर दिखाया गया, तो कई चीज़ों को हल्का किया गया, जिसमें नैरेटर की सेक्सुअलिटी भी शामिल थी, जिसे गे से बदलकर स्ट्रेट कर दिया गया था।

कैपोट का हॉली गोलाईटली के लिए एक अलग नज़रिया था। वह चाहते थे कि मर्लिन मुनरो यह रोल करें, लेकिन कहा जाता है कि उनके एक्टिंग कोच ने इसके खिलाफ सलाह दी थी, यह कहते हुए कि मुनरो को 'शाम की लेडी' का रोल नहीं करना चाहिए। शर्ली मैकलेन और किम नोवाक जैसे दूसरे एक्टर्स ने भी हेपबर्न को कास्ट करने से पहले यह रोल करने से मना कर दिया था, इस चॉइस की बाद में कैपोट ने सबके सामने बुराई की थी।

फिल्म की रिलीज़ से पहले, पैरामाउंट पिक्चर्स ने हॉली गोलाईटली की इमेज को बदलने की पूरी कोशिश की, और इस कैरेक्टर को कैपोट के ज़्यादा भड़काऊ किरदार से अलग रखा। स्टूडियो पब्लिसिटी हेपबर्न के एलिगेंट, प्रिंसेस जैसे पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी, यहाँ तक कि ऐसे स्टेटमेंट भी जारी किए गए जो मशहूर थे, 'स्टार ऑड्रे हेपबर्न हैं, टॉड्री हेपबर्न नहीं।'

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, 'अगर मैं नहीं रोकता तो भारत-पाक युद्ध में मारे जाते 3.5 करोड़ लोग'

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने खुद को एक 'शांतिदूत' के रूप में पेश किया है। मंगलवार को अपने 100 मिनट से अधिक लंबे 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध टल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते।

मंगलवार को अपने 100 मिनट से अधिक लंबे 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच युद्ध को रोकने में मदद की जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। ट्रंप ने कहा, "अपने पहले 10 महीनों में मैंने आठ युद्ध समाप्त कराए.. जिनमें पाकिस्तान और भारत का संघर्ष भी शामिल है, जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते।" अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी इसी तरह के दावे कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ ने परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मदद करके लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया था। इससे पहले ट्रंप ने इससे कम आंकड़े बताए थे। उन्होंने एक बार पहले 2.5 करोड़ और बाद में एक करोड़ के आंकड़े का उल्लेख किया था।

ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय खुद को कई बार दे चुके हैं। यह दावा वह पिछले साल 10 मई से अब तक लगभग 100 बार कर चुके हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में हुई "देर रात" की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान "पूर्ण और तत्काल" युद्धविराम पर सहमत हुए हैं। भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है। अपने संबोधन में ट्रंप ने कई अन्य संघर्षों को भी सूचीबद्ध किया, जिन्हें सुलझाने में उन्होंने मदद करने का दावा किया। इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा तथा गाजा में युद्ध शामिल हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब "बहुत निम्न स्तर" पर जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका देश और विदेश में सुरक्षा बहाल कर रहा है। राष्ट्रपति ने 'व्हाइट हाउस' (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में कहा, "हम गर्व से अपने देश में अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल कर रहे हैं और विदेशों में भी अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा देश पहले से कहीं अधिक मजबूत है।" ट्रंप के संबोधन के दौरान डेमोक्रेटिक सांसदों के बाधा डालने पर उन्होंने कहा, "यह मजाक नहीं है। ये बेचारे लोग।

युद्ध के 5वें वर्ष में जेलेंस्की की ट्रंप से अपील आप हमारे साथ खड़े रहें, पुतिन एक व्यक्ति नहीं

मॉस्को। रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे वर्ष की वर्षगांठ पार कर पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है। शांति वार्ता ठप है और क्षेत्रीय रियायतों पर कीव सख्त रुख बनाए हुए है।कीव में दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मैं चाहता हूं कि वह हमारे पक्ष में बने रहें।' उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उस राष्ट्र के साथ खड़ा रहे जो 'एक व्यक्ति' के खिलाफ लड़ रहा है। उनका इशारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर था। जेलेंस्की ने कहा, 'पुतिन एक व्यक्ति नहीं पूरा युद्ध हैं। सब कुछ एक व्यक्ति के बारे में है।'रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉशिंगटन में यह सुझाव दिया गया कि यदि यूक्रेन कुछ क्षेत्रीय रियायतें दे या चुनाव कराए तो संघर्ष कम हो सकता है।लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा कि पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र छोड़ना लगभग 2 लाख नागरिकों को असुरक्षित छोड़ने जैसा होगा।उनका संदेश स्पष्ट था कि 'रूस चाहता है कि हम अपनी सेना हटा लें। हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम बच्चे नहीं हैं।'यह बयान दर्शाता है कि कीव किसी भी शांति समझौते में अतिरिक्त जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। बता दें कि 24 फरवरी को रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के चार वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने 'तीन दिन में कीव लेने' की जो योजना बनाई थी।

, वह असफल रही। उन्होंने कहा, 'हमने अपनी स्वतंत्रता बचाई है, अपनी राज्य व्यवस्था नहीं खोई। पुतिन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए।' यूक्रेन मानता है कि युद्ध के परिणाम को आकार देने में अमेरिका की भूमिका निर्णायक है। जेलेंस्की ने संकेत दिया कि रूस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला जा रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की नीति आने वाले महीनों में निर्णायक साबित हो सकती है। जेलेंस्की ने अंत में कहा कि 'हम शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे। ग्लोरी टू यूक्रेन!'युद्ध अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन चुका है।

असम के कछार में अज्ञात शरारती तत्वों ने नेहरू की प्रतिमा तोड़ी, कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला

सिल्चर (असम)। असम के कछार जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, जिससे राजनीतिक आक्रोश फैल गया। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस मामले को लेकर सरकार की चुप्पी को चिंताजनक बताया। गोगोई ने कहा कि इस कृत्य से उस स्वाधीनता सेनानी की विरासत का अपमान हुआ है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी।

घटना कहां हुई और पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की रात बराक घाटी क्षेत्र के लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाइलापूल बाजार इलाके में हुई। पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उस खुदाई मशीन को जब्त किया है, जिससे प्रतिमा उखाड़ी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई में नरमी बरतने का आरोप लगाया है। लखीपुर थाना प्रभारी शंकर दयाल ने पीटीआई से कहा, हमें घटना का कोई चश्मदीद नहीं मिला है। हालांकि, व्यापार संघ के एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ अज्ञात लोग खुदाई मशीन की मदद से प्रतिमा तोड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दयाल ने कहा, हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और मशीन जब्त कर ली गई है, लेकिन चालक को अभी पकड़ा नहीं जा सका है।

असम कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतिमा को नष्ट करने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान नेता और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का अपमान है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। गोगोई ने आगे कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अनैतिक कार्यों के जरिये लोकतांत्रिक इतिहास को मिटाने की कोई भी कोशिश स्वीकार्य नहीं है।

पाकिस्तान में नया कमाल! फर्जी डिग्री वाला जज 5 साल तक सुनाता रहा फैसले, हाई कोर्ट ने खोली पोल

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। पाकिस्तान से न्याय व्यवस्था को हिला देने वाला मामला सामने आया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी)ने 23 फरवरी को 116 पन्नों का विस्तृत फैसला जारी कर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके पद से हटा दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उनकी कानून की डिग्री शुरू से ही अमान्य थी, इसलिए हाई कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति भी कानूनी तौर पर अवैध थी।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को कराची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मूल शैक्षणिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए। जांच में पाया गया कि 1988 में उन्होंने फर्जी नामांकन नंबर से परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े गए।1989 में विश्वविद्यालय ने उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।इसके बाद भी उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी जारी रखी।अगले वर्ष उन्होंने 'तारिक जहांगीरी' नाम से परीक्षा दी और एक ऐसा एनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया जो किसी अन्य छात्र इम्तियाज अहमद को जारी हुआ था।

गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी अदालत को बताया कि जहांगीरी कभी उनके संस्थान में विधिवत दाखिल ही नहीं हुए थे। अदालत ने कहा कि जस्टिस जहांगीरी को कई अवसर दिए गए कि वे अपने मूल दस्तावेज और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। लेकिन उन्होंने फुल बेंच की मांग की, चीफ जस्टिस को मामले से अलग करने की अपील की, सुनवाई टालने की कोशिश की, और कहा कि संबंधित मामला सिंध उच्च न्यायालय में लंबित है। बेंच ने इन प्रयासों को 'सुनवाई में देरी की रणनीति' बताया।

कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके थे, तो यह जिम्मेदारी जज की थी कि वे अपनी डिग्री को वैध साबित करें।

ट्रंप ने हादसे में घायल बच्ची को किया सम्मानित! कहा-प्रवासी भारतीय ट्रक चालकों पर कसेगा शिकंजा, बनेगा 'दलीला कानून'

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे एक भारतीय ट्रक चालक द्वारा कई वाहनों को टक्कर मारने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई एक छोटी बच्ची को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के मौके पर सम्मानित किया। इस दुर्घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और फिलहाल वह दिव्यांग के रूप में जीवन जी रही है। यूएस कैपिटल (संसद परिसर) में अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में ट्रंप ने कहा कि जून 2024 में 18 पहिए वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर ने बच्ची की खड़ी कार को टक्कर मार दी थी। उन्होंने बताया कि दलीला कोलमैन तब केवल पांच साल की थी।

उन्होंने कहा, "ट्रक चालक एक अवैध प्रवासी था जिसे जो बाइडन ने देश में आने दिया था और कैलिफोर्निया के खुली सीमा के पक्षधर नेताओं ने उसे वाणिज्यिक चालक का लाइसेंस दिया था।" अपने संबोधन में हालांकि ट्रंप ने चालक की पहचान नहीं बताई। पिछले साल अगस्त में अमेरिका में अवैध रूप से आए प्रताप सिंह को कैलिफोर्निया में ट्रैक्टर-ट्रेलर को चलाते समय कई वाहनों को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कोलमैन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ट्रंप ने कहा कि चिकित्सकों ने कहा था कि कोलमैन कभी चल-फिर या बोल नहीं पाएगी और न ही वह पहले की तरह बेहतर जीवन जी पाएगी। उन्होंने कहा, "वह खाना भी नहीं खा पाती। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अब पहली कक्षा में है, चलना सीख रही है और आज शाम अपने पिता के साथ यहां हमारे बीच है... कोलमैन आप एक प्रेरणा हो।" वहां मौजूद सांसदों, विशेष अतिथियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर कोलमैन का स्वागत किया। ट्रंप ने कहा कि कई "अवैध प्रवासी" अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और दिशा, गति, खतरे या स्थान के बारे में सबसे बुनियादी सड़क संकेतों को भी नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, "इसीलिए आज रात मैं कांग्रेस से अपील कर रहा हूं कि वह एक विधेयक पारित करे जिसे हम 'दलीला कानून' कहेंगे, जो किसी भी राज्य को अवैध प्रवासियों को वाणिज्यिक चालक लाइसेंस जारी करने से रोकगा।"

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)